



निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 29 पटना, बुधवार, 28 आषाढ़ 1939 (श0)
19 जुलाई 2017 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-7	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9—विज्ञापन ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 8-14
भाग-4—बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क 15-38

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

12 जुलाई 2017

सं० 6/गो०-34-05/2016-2441—बिहार वित्त सेवा के सहायक आयुक्त कोटि के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष संतम्भ 6 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	बैच/ वरीयता	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री योगेन्द्र प्रसाद, वा०-कर सहायक आयुक्त	विशेष	पटना	वा०-कर सहायक आयुक्त, मधुबनी अंचल, मधुबनी	वा०-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
2.	श्री मकेश्वर शर्मा, वा०-कर सहायक आयुक्त	विशेष	लखीसराय	कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा	वा०-कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार
3.	श्री प्रभात कुमार, वा०-कर सहायक आयुक्त	विशेष	पूर्णियाँ	कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया	वा०-कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजीत कुमार राम, उप-सचिव।

12 जुलाई 2017

सं० 6/गो०-34-05/2016-2442—बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर पदाधिकारी कोटि के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष संतम्भ 6 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	बैच/ वरीयता	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राज किशोर साह, वाणिज्य-कर पदाधिकारी	विशेष	मुजफ्फरपुर	कोषागार पदाधिकारी, नवगछिया	वा०-कर पदाधिकारी, अंकेक्षण, पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना
2.	श्री मुस्तर अकरम, वाणिज्य-कर पदाधिकारी	48 से 52वीं	हजारीबाग	वित्त विभाग, बिहार, पटना	वा०-कर पदाधिकारी, अंकेक्षण, मगध प्रमंडल, गया
3.	श्री मनोज कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी	तृतीय सीमित	पटना	वा०-कर पदाधिकारी समेकित जांच चौकी, रजौली	वा०-कर पदाधिकारी, रक्सौल अंचल, रक्सौल
4.	श्री दयाशंकर सिंह, वाणिज्य-कर पदाधिकारी	तृतीय सीमित	भोजपुर	वा०-कर पदाधिकारी, रक्सौल अंचल, रक्सौल	वा०-कर पदाधिकारी, अंकेक्षण, पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना
5.	श्री सुकेश कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी	53 से 55वीं	खगड़िया	वा०-कर पदाधिकारी, समेकित जांच चौकी, जलालपुर	वा०-कर पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजीत कुमार राम, उप-सचिव।

12 जुलाई 2017

सं० 6/गो०-34-05/2016-2443—बिहार वित्त सेवा के उपायुक्त कोटि के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष संतम्भ 6 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	बैच/ वरीयता	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री इन्द्र नारायण झा, वा०—कर उपायुक्त	36वीं	सहरसा	वा०—कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	वा०—कर उपायुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
2.	श्री कमल किशोर चौधरी, वा०—कर उपायुक्त	37वी०	गया	कोषागार पदाधिकारी, रोहतास	वा०—कर उपायुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना
3.	श्री मोती लाल, वा०—कर उपायुक्त	37वीं	गोपालगंज	वा०—कर उपायुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना	लेखा पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली
4.	श्री बिपिन कुमार झा, वा०—कर उपायुक्त	37वी०	दरभंगा	वा०—कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	वा०—कर उपायुक्त (प्रभारी), मधेपुरा अंचल, मधेपुरा
5.	श्री किशोर कुमार सिन्हा, प्रभारी वा०—कर उपायुक्त	37वीं	पटना	वा०—कर उपायुक्त (प्रभारी), गोपालगंज अंचल, गोपालगंज	वा०—कर उपायुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना
6.	मो० असदुज्जमां, वा०—कर उपायुक्त	विशेष	सारण	जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, कटिहार	वा०—कर उपायुक्त, समेकित जांच चौकी, कर्मनाशा में पदस्थापित करते हुए अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, गया में प्रतिनियुक्ति
7.	श्री क्यामुल हक अंसारी, वा०—कर उपायुक्त	विशेष	अररिया	कोषागार पदाधिकारी, निर्मली	वा०—कर उपायुक्त (अंकेक्षण), सारण प्रमंडल, छपरा
8.	श्री संजय कुमार प्रसाद, वा०—कर उपायुक्त	विशेष	सारण	जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना	वा०—कर उपायुक्त, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, मुख्यालय, बिहार, पटना
9.	श्री विजय कुमार, वा०—कर उपायुक्त	विशेष	पटना	सहायक आयुक्त, भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन, पटना	वा०—कर उपायुक्त (प्रभारी), गोपालगंज अंचल, गोपालगंज
10.	श्री जय शंकर सिंह, वा०—कर उपायुक्त	विशेष-02	खगड़ियाँ	कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर	वा०—कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
11.	श्री प्रमोद कुमार, वा०—कर उपायुक्त	विशेष-02	देवधर	कोषागार पदाधिकारी, अरबल	वा०—कर उपायुक्त, आर्थिक अन्वेषण इकाई, मुख्यालय, बिहार, पटना।
12.	श्री राजीव रंजन, वा०—कर उपायुक्त	विशेष	अररिया	वा०—कर उपायुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	वा०—कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अजीत कुमार राम, उप—सचिव।

12 जुलाई 2017

सं० 6/गो०-34-05/2016-2444—बिहार वित्त सेवा के संयुक्त आयुक्त कोटि के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष संतम्भ 6 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	बैच/वरीयता	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कृष्ण कान्त गुप्ता, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	32वी0	देवधर	वा0—कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण) भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य—कर विभाग, मुख्यालय पटना
2.	श्री अनिल कुमार, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	32वी0	भोजपुर	वा0—कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), सारण प्रमंडल, छपरा	वा0—कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), सारण प्रमंडल सारण अतिरिक्त प्रभार, वा0—कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
3.	श्री सियाराम सिंह, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	32वी0	भोजपुर	वा0—कर संयुक्त आयुक्त (अपील) मगध प्रमंडल	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, समेकित जांच चौकी, कर्मनाशा
4.	श्री पाण्डेय संतोष कृष्ण सहाय, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	33वी0	पटना	लेखा पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली,	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य—कर विभाग, मुख्यालय पटना
5.	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	34वी0	सिवान	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, (अंकेक्षण), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	वा0—कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), सारण प्रमंडल, छपरा
6.	श्री बिनोद पाठक, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	34वी0	भोजपुर	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, (अंकेक्षण), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, (अपील), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
7.	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	34वी0	वाराणसी	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, समेकित जांच चौकी, जलालपुर	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य—कर विभाग, मुख्यालय पटना
8.	श्री विपीन कुमार सिंह, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	35वीं	बेगुसराय	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, समेकित जांच चौकी, डोभी	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, (अंकेक्षण), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ
9.	श्री जीवन अग्रवाल, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	35वी0	दरभंगा	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य—कर विभाग, मुख्यालय पटना अतिरिक्त प्रभार वा0—कर संयुक्त आयुक्त, (अंकेक्षण), मगध प्रमंडल, गया
10.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	36वी0	सहरसा	वा0—कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य—कर विभाग, मुख्यालय पटना	वा0—कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
11.	श्री सुनील कुमार सिंह, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	36वी0	पटना	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, (प्रशासन) सारण प्रमंडल, छपरा	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, पटना
12.	श्री अयोध्या पासवान, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	36वी0	मुंगेर	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, (अपील) भागलपुर प्रमंडल	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, (अपील) मगध प्रमंडल, गया
13.	श्री सजन कुमार रूंगटा, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	36वी0	पूर्णियाँ	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, समेकित जांच चौकी, कर्मनाशा	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, (अंकेक्षण) भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
14.	श्री प्रमोद कुमार ग्वालिया, वा0 कर संयुक्त आयुक्त	36वीं	मुंगेर	वा0—कर संयुक्त आयुक्त, (अंकेक्षण), मगध प्रमंडल, गया	वा0—कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अजीत कुमार राम, उप—सचिव।

12 जुलाई 2017

सं० 6/गो०-34-05/2016-2445—बिहार वित्त सेवा के अपर आयुक्त कोटि के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष संतम्भ 6 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	बैच/ वरीयता	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नवपदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संजीव रंजन, वा० कर अपर आयुक्त	32वीं	बेगुसराय	वा०-कर अपर आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, पटना	वा०-कर अपर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय पटना
2.	श्री राजीव कुमार, वा० कर अपर आयुक्त	33वीं	पटना	वा०-कर अपर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय पटना	वा०-कर अपर आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, पटना

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजीत कुमार राम, उप-सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

7 जुलाई 2017

सं० ई2-207/82-2283—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश सं० 12/टि०-4-162/93- का०-467/पटना- 15, दिनांक 16.12.1998 में अंकित निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार निर्वाचन सेवा के निम्नांकित 03 (तीन) अवर निर्वाचन पदाधिकारियों की सेवा अवर निर्वाचन पदाधिकारी के मौलिक पद वेतनमान पी०बी०-2, रु० 9300-34800 ग्रेड पे०- रु० 4800/- पर उनके नाम के समक्ष स्तंभ 4 में अंकित तिथि से संपुष्ट करते हुए उनके चार वर्षों की सेवा एवं संपुष्टि के उपरान्त उक्त तिथि से ही वेतनमान पी०बी०-3, रु० 15600-39100, ग्रेड पे०-रु० 5400/- में उत्क्रमित किया जाता है (जो सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3590 दिनांक 24.05.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 से वेतन पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधानों से आच्छादित होगा)।

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/गृह जिला/वरीयता क्रमांक	पदस्थापन स्थल	सेवा संपुष्टि तथा वेतनमान पी०बी०-3 रु० 15600-39100/- एवं ग्रेड पे०-5400/- में उत्क्रमण की तिथि
1	2	3	4
1	श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव/ कटिहार/56/2013	अररिया अनुमंडल	14.04.2017
2	श्री सरफराज नवाज/ पटना/61/2013	औरंगाबाद सदर अनुमंडल	14.04.2017
3	श्री महेश कुमार पासवान/ पूर्णियाँ/71/2013	मधेपुरा सदर अनुमंडल	14.04.2017

2. यह सेवा संपुष्टि संबंधित पदाधिकारी की वरीयता का द्योतक नहीं होगा तथा इसका अन्य पदाधिकारियों की आपसी वरीयता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

15 जून 2017

सं० 01-बी०एम०डी०-180-17/99-1578/एम०—Bihar State Mineral Development Corporation Ltd. (बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड) के निदेशक पर्वद (Board of Directors) को तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए संशोधित किया जाता है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग से जारी अधिसूचना संख्या-5169/पटना, दिनांक 28.04.17 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1014/एम० पटना दिनांक 13.04.17 द्वारा गठित निदेशक पर्वद में श्रीमति हरजोत कौर बम्हरा, प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम के जगह पर श्री अतुल प्रसाद, प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम को अध्यक्ष पद पर नामित किया जाता है।

3. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-1014/एम०, दिनांक 13.04.17 से अधिसूचित सी०एम०डी० महोदया के अवकाश अवधि पर रहने के दौरान बी०एस०एम०डी०सी० के कार्यों के सम्पादनार्थ एतद् अधिसूचना संशोधित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार, अवर सचिव।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

अधिसूचना

22 जून 2017

सं० उ०नि०-12/2014-450—बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-24 में निहित प्रावधान के अनुसरण में "बिहार राजभाषा सहायक (उर्दू) संवर्ग", "बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग" तथा उर्दू निदेशालय के अधीन मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों को दिये गये दण्ड की अपील की सुनवाई के लिए सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार को विनिर्दिष्ट किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा, प्रधान सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

26 अप्रैल 2017

सं० 01/सह.राज.स्था.(स्थानान्तरण) 04/2015-1379—श्री संजय कुमार झा, सहायक निबंधक, स.स. (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को तत्कालीन प्रभाव से जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप-सचिव।

27 अप्रैल 2017

सं० 01/रा.स्था.बि.स.से.-पद-79/2007-1407—श्री दिनेश कुमार, सहायक निबंधक (अ.र.), स.स., बिहार, पटना को अपने आँखों के ईलाज के निमित्त दिनांक 31.07.15 से 22.06.16 तक उपभोगित अवकाश को महालेखाकार के अवकाश आदेयता प्रतिवेदन ज्ञापांक-12 Co-op-V, 16 दिनांक 09/2016 के आलोक में निम्न रूप से स्वीकृत किया जाता है।

(i) दिनांक 31.07.15 से 24.01.16 तक 178 दिनों का उपार्जित अवकाश।

- (ii) दिनांक 25.01.16 से 05.04.16 तक 73 दिनों का रूपान्तरित अवकाश।
(iii) दिनांक 06.04.16 से 22.06.16 तक 78 दिनों का उपार्जित अवकाश।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप-सचिव।

17 मई 2017

सं. 01/रा.स्था.(3) विविध-01/2010-1589—श्री कुमार शांत रक्षित, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., पटना के प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप-सचिव।

8 जून 2017

सं. 1/सह. (रा.) स्था. (अंके.) 14/98-1896—सहकारिता विभाग के अंतर्गत निम्नांकित अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ (वेतनमान पी.बी.-2, ग्रेड पे-4600) को बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ (वेतनमान पी.बी.-2, ग्रेड पे-4800) के पद पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है :-

क्र. सं.	नाम, /मूल कोटि का वरीयता क्रमांक	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री गोपाल प्रसाद साह 421	मुंगेर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0 खगड़िया
2	श्री रतन कुमार 433	बेगूसराय	संयुक्त निबंधक (अंके.), स0स0 पटना प्रमंडल, पटना
3	श्री मो0 इम्तियाज अहमद 450	पटना	उप मुख्य अंकेक्षक, स0स0 बिस्कोमान, पटना
4	श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी 451	भोजपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0 पटना
5	श्री चन्द्रमोहन कुँअर 455	दरभंगा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0 मधुबनी
6	श्री अंजनी कुमार सिन्हा 457	मुजफ्फरपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0 समस्तीपुर
7	श्री अजेय कुमार सिन्हा 458	दरभंगा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0 बेगूसराय
8	श्री श्यामानन्द साह 463	पूर्णिया	उप अंकेक्षक, स0स0 बि0रा0सह0 बैंक, पटना
9	श्री बुच्चन झा 464	मधुबनी	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0 सहरसा
10	श्री सुनील कुमार जायसवाल 465	पटना	निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना
11	श्री रविन्द्र कुमार लाभ 468	सीतामढ़ी	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0 समस्तीपुर
12	श्री जयनाथ सिंह 472	भोजपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0 पटना
13	श्री सुधीर कुमार, 475	मुंगेर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0 पटना
14	श्री सत्यनारायण प्रसाद 479	पटना	उप मुख्य अंकेक्षक, स0स0 बि0रा0गृह निर्माण एवं औद्योगिक सहकारी फंडरेशन, पटना
15	श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा 480	सारण	निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना
16	श्री शशिभूषण प्रसाद 482	पटना	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0 कटिहार

2. यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन SLP (C) संख्या 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

3. उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिये जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ में उत्क्रमित करते हुये उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4. उपर्युक्त नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 18—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

अधीक्षक का कार्यालय
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

निविदा सूचनाएं
29 जून 2017

सं० 6618—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के आई०जी०सी०सी० इमरजेन्सी के पीछे रैन बसेरा के उपरी तल्ला पर रोगियों एवं परिजनों के सुविधा हेतु रोगी कल्याण समिति की बैठक में लिये निर्णयों के आलोक में डॉ० रामनरेश यादव सस्ता भोजनालय/खान-पान दुकान खोलने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक व्यक्ति निविदा प्रकाशित होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर स्पीड-पोस्ट एवं निबंधित डाक द्वारा जमा करेंगे। विलम्ब से प्राप्त निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

निविदा की आवश्यक शर्तें एवं सूची अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में मिलकर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

स्थान :-

- (1) आई०जी०सी०सी० इमरजेन्सी के पीछे रैन बसेरा के उपरी तल्ला पर

निविदा की आवश्यक शर्तें

- (1) निविदा दो प्रकार की होगी—तकनीकी एवं वित्तीय। दोनों ही निविदा अलग-अलग लिफाफे में टंकित एवं मुहरबन्द होगा। एक लिफाफे में दोनों निविदा देने पर वह स्वतः रद्द समझा जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे।
- (2) निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या निविदा में अंकित करना होगा तथा वित्तीय निविदा में खान-पान सामग्रियों का दर संबंधित पत्र डालना होगा तथा शेष शर्तें अनुरूप दस्तावेज तकनीकी निविदा में डालना होगा।
- (3) निविदादाता को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- (4) पहचान पत्र के रूप में वोटर आई कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड में से एक होना चाहिए।
- (5) आवेदन के साथ 10,000=00 (दस हजार) रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। (रैन बसेरा हेतु)
- (6) दूकान का मासिक किराया, सरकार द्वारा निर्धारण अनुसार देय होगा।
- (7) दूकान 05(पाँच) वर्ष के लिए आवंटित होगा। संतोषप्रद कार्य होने पर पाँच साल के बाद दोबारा 05 (पाँच) वर्ष के लिए अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- (8) प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की दर से किराया बढ़ोतरी होगी।
- (9) दूकान में हीटर आदि का प्रयोग नहीं करना होगा। बिजली का मीटर स्वयः लगाना होगा। तथा बिजली बील का भुगतान स्वयः करना होगा।
- (10) दुकान में शुद्ध पेय जल हेतु वाटर कुलर के साथ आर०ओ० मशीन स्वयः लगाना होगा।
- (11) दुकान में कुर्सी टेबल फर्नीचर की व्यवस्था स्वयः करना होगा, एवं खाना बनाने का कार्य उपरी प्लोर पर होगा।
- (12) खाना बनाने का कार्य L.P.G गैस पर ही करना होगा।
- (13) रैन बसेरा (दुकान) का साफ-सफाई स्वयं करना होगा।
- (14) नाश्ता का दर 20=00 (बीस) रु० निर्धारित होगा तथा खाना का दर 40=00 (चालीस) रु० एवं चाय का दर 05=00 (पाँच) रु० निर्धारित होगा।
भोजन एवं नाश्ता का निर्धारित दर से कम दर अंकित निविदा स्वीकृत किये जायेंगे।

(15) नाश्ता एवं खाना में निम्नलिखित खाद्य सामग्री आपूर्ति करना होगा।

(क) नाश्ता—04 कचौरी+02जलेबी+01सब्जी/02 रोटी (50 ग्राम आटा/रोटी) + 01 सब्जी/छोले+01 भुदुरे

(ख) खाना—02 रोटी+100 ग्राम चावल/150 ग्राम चावल + दाल (01 कटोरी)+भुजिया+सीजनल हरी सब्जी/चना धुधनी/आलु मटर/आलु चना

- (16) खान-पान दूकान के लिए फुड निरिक्षण से लाईसेंस दूकान आवंटित होने के बाद देना होगा।
- (17) निविदादाता को कम से कम खान-पान दूकान चलाने का तीन साल का अनुभव होना चाहिए।
- (18) किसी भी कारण से अस्पताल को नुकसान पहुँचाने पर जुर्माना लगेगा।
- (19) इन दूकानों का सूचारु रूप से नियमानुसार चलाने के लिए एक तीन सदस्यीय कमिटी करेगी। जिसमें अस्पताल का दोनों उपाधीक्षक एवं एक मुख्य आकस्मिक चिकित्सा पदाधिकारी रहेंगे।
- (20) थाना/वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचारण प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- (21) किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।

आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।

निविदा सूचना

22 जून 2017

सं० 6359—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के विभिन्न विभागों में वित्तीय वर्ष 2017-18 अन्तर्गत उपयोग आने वाले विविध सामग्री, विद्युत सामग्री, लीलेन सामग्री एवं उपस्करों के क्रय हेतु बिहार वाणिज्यकर एवं जी०एस०टी० में निबंधित निर्माताओं, प्राधिकृत विक्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद कम्प्युटराईज टंकित निविदा, प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर सरकारी डाक से निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सभी आवश्यक वॉछित अभिलेखों के साथ आमंत्रित किया जाता है।

निविदा चार कोटि में होगी। कोटी-ए०—विविध सामग्री, कोटी-बी०—विद्युत सामग्री, कोटी-सी०—लीलेन सामग्री एवं कोटी-डी०—उपस्कर। प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग निविदा देय होगा। प्रत्येक कोटिवार निविदा दो भागों में होगी, तकनीकी एवं वित्तीय निविदा। दोनों ही निविदा अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद तथा लिफाफे के उपर कोटि (ए०, बी०, सी०, डी०) एवं विषय (विविध सामग्री, विद्युत सामग्री, लीलेन सामग्री एवं उपस्करों सामग्री) हेतु तकनीकी निविदा/वित्तीय निविदा सुस्पष्ट रूप से अंकित रहना अनिवार्य होगा। एक ही लिफाफे में दोनों निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) खुला रूप में पाये जाने पर निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा। निविदा सिर्फ सरकारी डाक से निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के आलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा या फटा/खुला निविदा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। साथ ही निविदा में संलग्न सभी अभिलेख पूर्ण रूप से विषय सूची के साथ पृष्ठांकित होगी। इस निविदा के संबंध में सारी जानकारीयों बिहार सरकार के वेबसाइट—www.prdbihar.org/www.prdbihar.gov.in एवं पी०एम०सी० एच० के वेब साइट—www.pmch.in पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निविदा प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को क्रय शाखा से निविदा शर्त एवं सूची प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा शर्त

निविदा चार कोटी में होगी। कोटी-ए०—विविध सामग्री, कोटी-बी०—विद्युत सामग्री, कोटी-सी०—लीलेन सामग्री एवं कोटी-डी०—उपस्कर। प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग निविदा देय होगा। प्रत्येक कोटिवार निविदा दो भागों में होगी। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा। दोनों ही निविदा अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद तथा लिफाफे के उपर कोटि (ए०, बी०, सी०, डी०) एवं विषय (विविध सामग्री, विद्युत सामग्री, लीलेन सामग्री एवं उपस्करों सामग्री) हेतु तकनीकी निविदा/वित्तीय निविदा सुस्पष्ट रूप से अंकित रहना अनिवार्य होगा। दोनों ही निविदा अलग-अलग लिफाफे में कम्प्युटर टंकित एवं मुहरबन्द होगा। एक लिफाफे में दोनों निविदा खुला रहने पर वह स्वतः रद्द समझा जायेगा। लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से तकनीकी एवं वित्तीय लिखने के साथ-साथ निविदा का विषय अंकित करना होगा। और लिफाफे पर निविदा दाता का नाम, पूरा पता के साथ अंकित करना होगा।

तकनीकी निविदा

1. बिहार वाणिज्य कर विभाग एवं जी०एस०टी० में निबंधन होना अनिवार्य होगा। तदनुसार वाणिज्य कर विभाग एवं जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. बिहार वाणिज्य कर में निबंधित निविदादाता निविदा स्वीकृत होने के उपरांत वाणिज्य कर विभाग से अनापति प्रमाण पत्र/वाणिज्य कर चुकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. अगर निविदादाता निर्माता हैं, तो उद्योग विभाग का पंजीयन पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
4. लघु उद्योग इकाई को सरकार से मिलने वाली सुविधा से संबंधित कागजात संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता को कोटी-ए० के लिए 25,000=00 (पच्चीस हजार) रुपये, कोटी-बी० एवं सी० के लिए 50,000=00 (पचास हजार) रुपये एवं कोटी-डी० के लिए 1,00,000=00 (एक लाख) रुपये

- अग्रधन राशि तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अग्रधन राशि बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0 जो अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना के नाम से प्रतिभूत होगा।
6. निविदादाता को कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत मूल शपथ-पत्र "यह कि मेरा फर्म किसी भी क्रिमिनल केश/सरकारी/गैर सरकारी संस्थान द्वारा दंडित नहीं किया गया है एवं मेरे द्वारा निविदा में संलग्न किये गये सभी अभिलेख सही है।" संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कोटी के लिए अलग-अलग शपथ-पत्र देय होगा।
 7. अगर निविदादाता पूर्व में किसी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थान में आपूर्ति किये हों, तो उसका प्रमाण देना है।
 8. सभी सामग्रियों (जिनके सामने आई0एस0आई0/आई0एस0ओ0/सी0ई0 मार्क अंकित है) के लिए निर्गत सामग्रियों की सूची के अनुसार उनके नाम, निर्माता का नाम अंकित सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 10. वैसे निविदादाता जिन्हें किसी निर्माता कम्पनी द्वारा निविदा में भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया गया हो वैसे स्थिति में निर्माता कम्पनी का मूल प्राधिकार पत्र, जिसमें इस निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत किया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा साथ ही निर्माता कम्पनी का उद्योग विभाग का पंजीयन एवं अद्यतन प्रमाण-पत्र के साथ-साथ सामग्रियों का विशिष्टीकरण (स्पेसिफिकेशन) सहित निर्माता का कैंटलाक(जिसमें साफ तौर पर कोट किये गये सामग्रियों का माडल न0 अंकित होना चाहिए) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 11. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को आवश्यकतानुसार आंशिक या पूर्णतः अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
 12. निविदादाता द्वारा ग्रुप "सी0" एवं ग्रुप "डी0" में तकनीकी रूप से सफल होने के पश्चात् सभी Quoted सामग्रियों का नमूना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। समिति द्वारा नमूना चयन के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा। एजेन्सी द्वारा नमूना नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में वित्तीय निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा।
 13. निर्गत सामग्रियों की सूची के अनुसार क्रमवार इनका नाम एवं निर्माता का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
 14. क्रय समिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति एवं नमूना चयन के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
 15. स्वीकृत दर पर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
 16. सामान पहुँचाने का कोई अलग से शुल्क देय नहीं होगा।
 17. इन्कम टैक्स पैन नम्बर एवं विगत तीन वर्षों का अद्यतन जमा रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 18. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।

वित्तीय निविदा

वित्तीय निविदा में सामग्रियों का नाम निर्माता सहित प्रकार एवं उनके सामने कर रहित दर, (अंक एवं शब्दों में) अंकित करना होगा। शब्द में लिखे दर ही मान्य होगा। विशिष्टीकरण (स्पेसिफिकेशन) के लिए एक से अधिक दर अनुमान्य नहीं होगा। निविदादाता सिर्फ उच्च कोटि के गुणवत्तायुक्त सामग्रियों का दर प्रेषित करेंगे। निविदादाता को वित्तीय निविदा के साथ इस आशय का शपथ पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न करना होगा कि निविदा में अंकित दर एम0आर0पी0 से कम या बाजार दर पर मूल्यकृत है। मेरे फर्म द्वारा इस दर से कम दर पर किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में आपूर्ति नहीं की जा रही है।

सामग्रियों की सूची

CATEGORY-A

विविध सामग्री

1. वासिंग सोडा, टाटा ब्रान्ड/या समकक्ष
2. रील थ्रेड-वर्दमान/मोदी या समकक्ष
3. एन0एम0टी0-थ्रेड नं0 40, वर्दमान/मोदी या समकक्ष
4. लाईफ ब्याय साबुन-बड़ा साईज, मेडिकेटेड
5. ताला, 7 लीभर/6 लीभर (लॉक/गोदरेज या इसे तरह के मानक निर्माता)
6. डी0एन0सी0 बॉल, वर्दमान/मोदी या समकक्ष
7. चेन थ्रेड नं0-10 वर्दमान/मोदी या समकक्ष
8. टार्च-बैट्री-एभररेडी/निप्पो या समकक्ष-1050 लीक प्रुफ
9. एल0एस0 बैट्री-1033,एभररेडी/निप्पो या समकक्ष, लीक प्रुफ
10. पेन्सिल बैट्री एभररेडी/निप्पो या समकक्ष, लीक प्रुफ
11. (A) टार्च मेटल-दो सेल, तीन सेल/पाँच सेल, एभररेडी/निप्पो या समकक्ष

- (B) टार्च (प्लास्टिक वॉडी)– दो सेल, तीन सेल/पाँच सेल, एभररेडी/निप्पो या समकक्ष
12. हवाई चप्पल–लखानी, रिलैक्सो/बाटा सभी साईज
13. निरमा सुपर–500 ग्राम पैक
14. मीठा सोडा–टाटा ब्रान्ड या समकक्ष
15. धोबी क्लॉथ इंक
16. टेबुल ग्लास 8 एम०एम०/12 एम०एम०
17. शीशे का ग्लास–एयरा या समकक्ष
18. कप प्लेट बोन चाईना या समकक्ष
19. टेलर मशीन आइल
20. डस्ट बीन कभर के साथ 14" ऊँचाई
21. भीम पाउडर, 500 ग्राम पैकेट
22. लाईफब्याय/डिटौल लिक्वूड हैंडवाश – बड़ा साईज
23. नमक (नन आयोडाईजड)
24. सर्फ एक्सल – 01 किलोग्राम का

CATEGORY-B

विद्युत सामग्री

1. सी०एफ०एल० बल्ब–23, 27, 28, 30, 35, 65, 75, एवं 85 वाट (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
2. इमरजेन्सी लाईट दो ट्यूब वाला (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/ सी०ई० मार्क)
3. चॉक 40 वाट (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/ सी०ई० मार्क)
4. रूम हीटर/1 रॉड/2 रॉड (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/ सी०ई० मार्क)
5. ट्यूब लाइट 4'X 36वाट/4 × 40 वाट/2 × 20 वाट (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
6. स्टार्टर 40 वाट (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/ सी०ई० मार्क)
7. 48" एवं 56" सीलिंग फैन (हैवेल्स/बजाज/उषा)
8. 2.5 MFD सीलिंग फैन का कन्डेंसर एल्लुमुनियम का (मानक निर्माता द्वारा निर्मित)
9. 3.15 MFD सीलिंग फैन का कन्डेंसर एल्लुमुनियम का (मानक निर्माता द्वारा निर्मित)
10. (A) पैडेस्टर फैन पुरा मेटल का (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/ सी०ई० मार्क)
(B) पैडेस्टर फैन फाईबर वॉडी का (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/ सी०ई० मार्क)
11. हीटर 1500 वाट मोटा तार लगा हुआ।
12. एक्सटेंशन कॉड दस मीटर तौबे का तार लगा हुआ।
13. हॉट एयर ब्लोयर (मानक निर्माता द्वारा निर्मित)
14. 250 वाट HPSV LAMP (फीलिप्स/बजाज)
15. 250 वाट HPSV चॉक (फीलिप्स/बजाज)
16. 250 वाट Ignitor (फीलिप्स/बजाज)
17. 5/6 amps one way F/T switch (Kany/Anchor)
18. 15/16 amps, 6 pin SS combined (Kany/Anchor)
19. 6 amps bell push (ISI/ISO/CE)
20. Call Bell (Ding dong)
21. 3 pin top 6 amps ISI (Anchor/Cona/Kany)
22. 3 pin top 15 amps ISI (Anchor/Cona/Kany)
23. 40 amps rating TPN, MCB 10 KA(Havells/HPL)
24. 63 amps rating TPN, MCB 10 KA(Havells/HPL)
25. 6 to 32 amps rating SP, MCB 10 KA(Havells/HPL)
26. PL lamp 36/40 watt (फीलिप्स/बजाज)
27. बॉल फैन (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
28. बल्ब 100 वाट (आई०एस०आई०/ आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
29. ट्यूब लाईट सेट (फटी, चौक, ट्यूब, स्ट्राटर)
30. एल०ई०डी० ट्यूब सेट
31. एल०ई०डी० ट्यूब
32. एल०ई०डी० बल्ब – 5 , 7 , 9 , 11 , 15 , 17 , 20 एवं अन्य

CATEGORY-C**लीलन सामग्री**

1. हरा कपड़ा 137 से०मी० अर्ज (पतला)
2. हरा कपड़ा 137 से०मी० अर्ज (मोटा)
3. हैन्ड टावेल 16" × 26" (उजला)
4. टावेल बड़ा साईज (उजला)
5. टावेल बड़ा साईज (रंगीन)
6. अपरन का कपड़ा टेरीकोट डॉक्टर्स एवं पारामेडिकल स्टाफ के लिए (उजला)
7. रबरसाईज क्वायर मैट्रेस (एक पीस में; दो पीस में)
साईज 36" × 78" × 3" (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ० ब्रान्ड)
8. रबरसाईज क्वायर मैट्रेस
साईज 54" × 30" × 3" (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ० ब्रान्ड)
दोनों ही मैट्रेस रेक्सिन कभर के साथ होगा।
9. खाकी ड्रील, जीन्स टाईप
10. डाक्टर्स के लिए कुर्ता, पैजामा, शुद्ध सूती
11. लाल ऊनी हरा ऊनी कंबल, वजन दो किलो वाशेबुल
12. डाक्टर्स के लिए लाइनिंग वाला चादर एवं तकिया का खोल (शुद्ध सूती)
13. पर्दा खिड़की का, साईन 48" × 54" टेरीकोट, पॉलिस्टर
14. मैकनी टॉस, डकबक/समकक्ष
15. प्लास्टिक गाऊन, डाक्टर्स के लिए
16. मच्छरदानी, साईज (40" × 82" × 60")
17. पीलो कभर साईज (16" × 26")
18. रैक्सीन कभर साईज 36" × 78" × 3" एवं 54" × 30" × 3"
19. दरवाजा पर्दा (बड़ा साईज)
20. पीलो साईज 15" × 24" सेमल एवं फाइबर
21. लेबर टेबुल का गद्दा (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ० ब्रान्ड)
22. कपड़ा का गाउन - (बड़े साईज का)
23. मारकीन कपड़ा (लाल एवं उजला)

CATEGORY-D**उपस्कर**

1. बेड साईड लॉकर (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
2. हॉस्पिटल आईरन बेड (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
3. अटेन्डेंट बेड (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
4. हॉस्पिटल आईरन बेड, बैक रेस्ट के साथ (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
5. पेडीएट्रिक बेड (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
6. एनेस्थेसिया ट्रॉली (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
7. मेडिसीन ट्रॉली (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
8. इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रॉली (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
9. स्ट्रेचर ट्रॉली (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
10. डाक्टर्स चेयर रिभालविंग (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
11. डाक्टर्स चेयर (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
12. हाफ एवं फुल सेक्रेटेरियट टेबुल (तीन ड्रावर के साथ)
13. रिभाल्विंग स्टूल चार लेग के साथ (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
14. प्लास्टिक स्टूल एवं चेयर (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
15. ऑफिस चेयर (उडेन)
16. मेकेनाईज्ड फुड ट्रॉली विथ एण्ड विथाउट वार्मर (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
17. स्टील आलमीरा 20 से 22 गेज गुड मेटल बेस वाला (मानक निर्माता द्वारा निर्मित)
18. लकड़ी का धोबी बॉक्स लम्बाई 3' चौड़ाई 2½' एवं ऊँचाई 3'
19. स्टील वाल एवं इनामेल वाल 36" से०मी० डाया (मानक निर्माता द्वारा निर्मित)
20. लीलेन सामग्री रखने के लिए स्टील बॉक्स स्टैन्ड के साथ
साईज 3½' लम्बा × 3' ऊँचा × 2½' चौड़ा (20 गेज)
21. वॉवेल स्टैन्ड सिंगल एवं डबल (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)

22. साईड स्क्रीन (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
23. किडनी ट्रे, स्टील एवं इनामेल-आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० ब्रान्ड
24. रेक्टेंगुलर ट्रे, स्टील एवं इनामेल (साईज-9"×6", 11"×7", 12"×8", 15"×12", 18"×12", 8"×3", 14"×10", 16"×4") आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क
25. व्हील चैयर (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
26. ड्रेसिंग टेबुल (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
27. हाईड्रोलिक ऑपरेशन टेबुल (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
28. ऑक्सीजन फ्लोमीटर (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
29. स्टील ट्रे विंग साईन, 18" × 12" (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
30. ड्रेसिंग ड्रम (स्टेनलेस स्टील) (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
9"× 9", 11"× 12", 15" × 12"
31. स्टील बॉल-45 सेंटीमीटर (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
32. साईडेक्स ट्रे-प्लास्टिक बड़ा साईज (मानक निर्माता द्वारा निर्मित)
33. बी०एच०टी० होल्डर, क्लोप के साथ (मानक निर्माता द्वारा निर्मित)
34. एक्स-रे भिन्न बाक्स (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
35. स्टील बेबी ट्रे (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
36. ऑक्सीजन सिलेन्डर ट्रॉली (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
37. आक्सीजन रिन्च
38. एक्जामिनेशन टेबुल (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
39. एक्जामिनेशन काउंच (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
40. आई० सी० यू० बेड (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
41. मलटीसीटर चैयर फूली आयरन विथ इपोकसीफिनिश (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/ सी०ई० मार्क)
42. लेबर टेबुल स्टेनलेस स्टील का मैट्रेस के साथ (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
43. अटेन्डेन्ट स्टूल पुरा स्टेनलेस स्टील का (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
44. क्रैस कार्ट (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
45. बेड पैन पुरा स्टेनलेस स्टील का (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
46. यूरीन पोट पुरा स्टेनलेस स्टील का (आई०एस०आई०/आई०एस०ओ०/सी०ई० मार्क)
47. यूरीन पोट (प्लास्टिक)

आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।

अधीक्षक का कार्यालय प्रेस एवं फॉर्म, गया

निविदा आमंत्रण सूचना

12 जुलाई 2017

सं० 148/प्र०—बिहार गवर्नमेंट प्रेस एवं फॉर्म गया के प्रयोजनार्थ वित्तिय वर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न प्रकार के कागजों के क्रय हेतु निर्माताओं / निर्माताओं के अधिकार प्राप्त एजेंटों एवं स्टॉकिस्टों से उनके लेटर पैड पर निम्नलिखित शर्तों पर द्वि-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदा दिनांक 12.08.17 को अपराह्न 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

(क) भाग - I लिफाफा - तकनीकी निविदा

(ख) भाग - II लिफाफा - वित्तिय निविदा

उपरोक्त दोनों प्रकार की निविदाएँ अलग अलग सील बंद लिफाफों में होनी चाहिए तथा लिफाफा पर तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा लिखा होना अनिवार्य है। सर्व प्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी जिनकी तकनीकी निविदा योग्य पाए जायेगे केवल उन्हीं की वित्तिय निविदा पर विचार किया जायेगा।

शर्तें:-

1. निविदा दिनांक 12.08.17 को 1.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किये जायेंगे तथा उसी दिन 3.00 बजे निविदा दाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी।

2. किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
 3. निविदा दाता को अभिकर्ता या स्टॉकिस्ट होने का प्रमाण पत्र/बिहार बिक्री कर /आय कर का अद्यतन भुगतान प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
 4. निविदा दाता को निविदा के साथ अधीक्षक प्रेस एवं फॉर्मस गया के नाम से प्लेज करा कर 50,000 (पचास हजार) रू० का एन०एस०सी०/ बैंक ड्राफ्ट(राष्ट्रीयकृत बैंक का) अग्रधन के रूप में संलग्न करना होगा।
 5. निविदा के साथ ए4 साईज में प्रत्येक कागजों का 10-10 सीट पेपर का स्पेसिफिकेशन एवं निविदा दाता का हस्ताक्षर एवं मुहर सहित नमूना के रूप में संलग्न करना होगा।
 6. कागज का दर, कर सहित एफ०ओ०आर० अधीक्षक प्रेस एवं फॉर्मस गया होना चाहिए। प्राप्त निविदा वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम तक मान्य होगा।
 7. सफल निविदादाताओं को कागज की आपूर्ति के लिए रोड परमिट स्वयं देना होगा।
 8. सफल निविदादाताओं को आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 1 माह के अन्दर पूरी सामाग्री आपूर्ति करनी होगी। सामाग्री पूर्ण रूप से आपूर्ति आदेश के अनुरूप प्राप्त होने के उपरान्त 90प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष 10 प्रतिशत की राशि का भुगतान केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान सहरणपूर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद किया जायेगा।
 9. निविदा की माँग की मात्रा को 20 प्रतिशत तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है। निविदा के संबंध में यदि किसी को मुकदमा दायर करना आवश्यक हुआ तो वह गया के अदालत में ही होगा।
- कागजों का पूर्ण विवरण एवं मात्रा इस प्रकार से है।

क्र०	कागजों का विवरण
1	मैपलिथो पेपर उजला रील में 62 से०मी० 70 जी०एस०एम०-200 मेट्रिक टन
2	मैपलिथो पेपर पिंक रील में 62 से०मी० 70 जी०एस०एम०-50 मेट्रिक टन
3	मैपलिथो पेपर पीला रील में 62 से०मी० 70 जी०एस०एम०- 30 मेट्रिक टन
4	मैपलिथो पेपर उजला रील में 43 से०मी० 70 जी०एस०एम०- 50 मेट्रिक टन
	कुल-330 मेट्रिक टन

आदेश से,

अरुण कुमार सिंह, अधीक्षक, प्रेस एवं फॉर्मस, गया।

सं० 860—मैं, **शिवानी**, पिता—श्री राजीव रंजन माता श्रीमति ऋतु नारायण, पता—ए/98, पी०सी० कॉलोनी कंकड़बाग, पो०—लोहिया नगर, थाना—कंकड़बाग, जिला—पटना—800020, (बिहार) शपथ—पत्र सं०—3653 दिनांक 17.03.2017 से मेरा नाम—शिवानी स्पृहा के नाम से जानी व पहचानी जाऊँगी वो भविष्य में मेरा सभी प्रकार के कार्यों व कागजातों में यही नाम इस्तेमाल किया जाएगा।

शिवानी।

No 860—I, **SHIVANI**, D/o Rajeev Ranjan, M/o Ritu Narayan R/o A/98 P.C. Colony Kankarbagh, P.O.- Lohianagar, PS- Kankarbagh, Dist.- Patna-800020, Bihar vide affidavit no. 3653 Dated. 17.3.2017 shall be known as Shivani Spriha for all future purpose.

SHIVANI.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 18—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

8 जून 2017

सं० 08/नि.को.(रा.)विभागीय-708/2016-1892—डा. श्रवण कुमार, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ—सह-जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक 21.10.2016 को रू. 50,000/- (पचास हजार रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं उनके विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-109/2016, दिनांक 21.10.2016, धारा-7/13(2)—सह-पठित धारा-13(1)(डी.)भ्र.नि. अधिनियम 1988 दर्ज होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 4074, दिनांक 23.11.2016 द्वारा दिनांक 21.10.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया है।

2. कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 19.04.17 के पूर्वाह्न में डा. कुमार के द्वारा अपना योगदान समर्पित किया गया है। सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(3)(1) के अन्तर्गत इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है। योगदान की तिथि से डा. कुमार निलंबन से मुक्त समझे जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, उप-सचिव (निगरानी)।

8 जून 2017

सं० 08/नि.को.(रा.)विभागीय-708/2016-1904—डा. श्रवण कुमार, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ—सह-जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक 21.10.2016 को रू. 50,000/- (पचास हजार रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं उनके विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-109/2016, दिनांक 21.10.2016, धारा-7/13(2)—सह-पठित धारा-13(1)(डी.)भ्र.नि. अधिनियम 1988 दर्ज होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 4074, दिनांक 23.11.2016 द्वारा दिनांक 21.10.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 19.04.17 के पूर्वाह्न में डा. कुमार के द्वारा अपना योगदान समर्पित किया गया है। सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(3)(1) के अन्तर्गत इनका योगदान विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1892 दिनांक 08.06.2017 द्वारा स्वीकृत करते हुए निलंबन मुक्त किया गया।

परन्तु चूँकि डा. कुमार के विरुद्ध ट्रेप केस के मामले में निगरानी थाना काण्ड संख्या-109/2016, दिनांक-21.10.2016, धारा-7/13(2)—सह-पठित धारा-13(1)(डी.)भ्र.नि. अधिनियम 1988 एवं धर्नाजन के मामले में निगरानी थाना काण्ड संख्या 124/2016 दिनांक 18.11.2016 धारा 13(2)—सह-पठित धारा 13(1)(ई.)भ्र.नि. अधिनियम 1988 दर्ज है तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जानी है। अतः इनका निलंबन जनहित में आवश्यक है ताकि जाँच कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1)(क) तथा 9(1)(ग) के अन्तर्गत उन्हें अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है ।

4. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा ।

5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, उप-सचिव (निगरानी)।

15 जून 2017

सं. 8/नि.को.(रा.)विभागीय-715/2013(खण्ड)1942—श्री अखिलेश कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., धनबाद, सम्प्रति सहायक निबंधक-सह-जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के द्वारा उक्त बैंक के प्रबंध निदेशक के पदस्थापन काल में वृहद पैमाने पर बैंक की राशि का दुर्विनियोग किया गया, जिसकी वसूली संदिग्ध है । फलस्वरूप सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1026, दिनांक 16.06.2006 द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र-“क”) गठित कर विधिसम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी । समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5027, दिनांक 31.10.2012 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री सी.के.अनिल, प्रशासक, बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । पुनः श्री शत्रुघ्न कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा अंतिम रूप से निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

पुनः प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2399, दिनांक 17.09.2013 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध फर्जी साख सहयोग समितियों के फर्जी सदस्यों को ऋण वितरण दिखाकर बैंक के करोड़ों रुपये के दुर्विनियोग के सहारे राशि की लूट, घोटाला एवं गबन के संबंध में एक अन्य आरोप-पत्र (प्रपत्र-“क”) गठित कर भेजा गया, जिसे विभागीय आदेशज्ञापांक 669, दिनांक 10.02.2014 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया गया ।

इस संदर्भ में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 5820, दिनांक 04.07.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन/अधिगम उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित सभी आरोप को अप्रमाणित बताते हुए अंकित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा सतर्कता नहीं बरती गई मृतप्राय समितियों को पुनर्जीवित किया जाना एक Progressive Step है, परन्तु इसे सतर्कता के साथ एवं चरणबद्ध तरीके से बैंक प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए था ।

समीक्षोपरान्त पाया गया कि जिस समिति के पास पहले से बकाया है उसकी वसूली किये बिना पुनः ऋण उपलब्ध कराना किसी भी दृष्टि से बैंक के हित में नहीं कहा जा सकता । श्री कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश की अवहेलना कर मोटर परिवहन सहयोग समितियाँ को तीन साल के लिए कैश क्रेडिट की सुविधा प्रदान करने की अनुशंसा की । इसके संबंध में जो निष्कर्ष संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया है, वह स्वीकार योग्य नहीं हो सकता । सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार ने अपने विभागीय मंतव्य में स्पष्ट कहा है कि समितियों पर ऋण रहने के बावजूद पुनः ऋण देना बैंक हित में नहीं है । मृतप्राय समिति को पुनर्जीवित कर ऋण स्वीकृत करने से बैंक को आर्थिक क्षति पहुँची है । अतएव यह मत कि मृतप्राय समितियों को पुनर्जीवित करने हेतु ऋण दिया जाना Progressive कदम है, स्वीकार योग्य नहीं हो सकता ।

प्रबंध निदेशक का यह दायित्व बनता है कि बैंक के हित की रक्षा करते हुए ऋण की स्वीकृति दें । दूसरे समिति के सदस्य रहते हुए भी सदस्य को ऋण स्वीकृत किया गया है । यह कहना कि इसकी जानकारी आरोपित पदाधिकारी को नहीं था, स्वीकार योग्य नहीं हो सकता । पूर्ण जाँच पड़ताल कर ही ऋण स्वीकृत किया जाना था, ताकि गलत सदस्यों/समितियों को ऋण स्वीकृत नहीं हो सके । आरोपित पदाधिकारी के इस कदम से बैंक को आर्थिक क्षति पहुँची है । इन्होंने स्थापित नियमों से परे जाकर बड़े बकायेदार समितियों एवं सदस्यों को ऋण स्वीकृत किया है । इनके आचरण में लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । इस लापरवाही एवं बैंक हित में कार्रवाई नहीं करने तथा बैंक के हित के विरुद्ध ऋण स्वीकृत करने के लिए वे दोषी हैं ।

अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अखिलेश कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., धनबाद, सम्प्रति सहायक निबंधक-सह-जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (यथासंशोधित 2007) के नियम 14(iv) के तहत 03(तीन) वर्षों की अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति का दण्ड संसूचित किया जाता है एवं उनके विरुद्ध संचालित इस विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है ।

2. इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, उप-सचिव (निगरानी) ।

20 जून 2017

सं. 8/नि.को.(रा.)विभागीय-704/2015-2011—श्री मनोज कुमार, बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति निलंबित को दिनांक 12.03.2015 को धान अधिप्राप्ति में किसानों के भुगतान हेतु पैक्सों/व्यापारमंडलों के लिए कैश क्रेडिट स्वीकृत करने की अनुशंसा करने के एवज में परिवादी श्री सुरेश कुमार, अध्यक्ष, व्यापार मंडल सत्तर कटैया, थाना-बिहरा, जिला-सहरसा से 70,000*00 (सत्तर हजार) रुपये घूस लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा श्री कुमार के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-020/2015 दिनांक 12.03.2015 दर्ज किये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या 1228 दिनांक 10.04.15 द्वारा उन्हें दिनांक 12.03.2015 के प्रभाव से निलंबित किया गया। कारागार से मुक्ति के फलस्वरूप श्री कुमार द्वारा योगदान समर्पित किया गया। श्री कुमार के विरुद्ध विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दिये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जानी थी। अतएव विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2083, दिनांक 25.06.2015 द्वारा श्री कुमार को पुनः अगले आदेश तक निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2086 दिनांक 26.06.2015 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-5539 दिनांक-22.06.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन/अधिगम समर्पित किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में निष्कर्षतः अभिमत है कि "सम्प्रति यह मामला न्यायिक प्रक्रियाधीन है, जिसकी साक्ष्य एवं प्रमाणिकता न्यायालय द्वारा ही स्थापित की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा के रूप में आरोपित पदाधिकारी एवं परिवादी के बीच अधिप्राप्ति कार्य संबंधी संबंध रहे हैं। साथ ही, घटना के दिन जब वे अधिप्राप्ति कर रही समितियों के पर्यवेक्षण/अनुश्रवण हेतु क्षेत्रीय भ्रमण में थे तो परिवादी के बुलाने पर वे बैजनाथपुर चौक गए तथा मंदिर में परिवादी से वार्ता की गई, जबकि एक विभागीय अधिकारी से यह अपेक्षित था कि वे अपनी गतिविधि विभागीय भ्रमण के दौरान कार्य स्थल तक सीमित रखते। क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपने कार्यक्षेत्र/कार्यस्थल (पैक्स/व्यापारमंडल आदि अधिप्राप्ति में संलग्न समितियों) से भिन्न स्थान पर परिवादी से मिलना आरोपित के विरुद्ध आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण बरतने का परिचायक प्रमाणित होता है।"

3. संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित उक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्र संख्या 2816 दिनांक 05.08.2016 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के अधिगम एवं उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त कदाचार के गम्भीर प्रमाणित आरोपों के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :-

- (क) उपर्युक्त गम्भीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(XI) के तहत सेवा से बर्खास्त किये जाने का दण्ड।
- (ख) निलंबन अवधि (दिनांक 12.03.2015 से बर्खास्तगी की तिथि तक) के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वहन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

उपरोक्त दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. चूँकि श्री कुमार समूह-क के पदाधिकारी हैं एवं इनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की अनुशंसा पर हुई थी, अतएव श्री कुमार के विरुद्ध अनुमोदित दण्ड पर विभागीय पत्रांक 3903, दिनांक 04.11.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति माँगी गयी।

उप-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 3338/लो.से.आ., दिनांक 13.02.2017 द्वारा आरोपित पदाधिकारी के सेवा से बर्खास्तगी संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति दी गई है।

6. दिनांक 06.06.2017 को मंत्रिपरिषद् की बैठक केमद संख्या-5 में विभागीय दण्ड के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

7. अतः श्री मनोज कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति निलंबित जिनका विवरणी नीचे अंकित है, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :-

1. उपर्युक्त गम्भीर आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (XI) के तहत सेवा से बर्खास्त किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
2. निलंबन अवधि (दिनांक 12.03.2015 से सेवा बर्खास्तगी तक) के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।
 - (i) सरकारी सेवक का नाम :- श्री मनोज कुमार
 - (ii) सरकारी सेवक की जन्म तिथि :- 01.04.1971
 - (iii) सरकारी सेवा धारण की तिथि :- 01.12.1995
 - (iv) सरकारी सेवक के पिता का नाम :- श्री रामचन्द्र प्रसाद
 - (v) स्थायी पता :- ग्राम+पो.-धनकडोभ, थाना-घोसवरी, जिला-पटना, पिन-803302

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, उप-सचिव (निगरानी)।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

19 अप्रैल 2017

सं० 22/नि0सि0(मुज0)-06-10/2012-550—श्री माखन लाल गुप्ता (आई०डी०-3938) तत्कालीन सहायक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरुद्ध उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान वर्ष 2012 में तिरहुत मुख्य नहर के वि०दू० 679.50 पर कराये जा रहे कैनाल लाईनिंग कार्यों में बरती गयी अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल, पटना द्वारा की गयी। उड़नदस्ता अंचल, पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-658, दिनांक 11.06.2013 द्वारा श्री गुप्ता से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री गुप्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०-1828, दिनांक 04.12.14 द्वारा श्री गुप्ता के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के निम्न बिन्दुओं पर श्री गुप्ता से विभागीय पत्रांक-1068, दिनांक 10.6.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

(1) Is code -5454 के अनुसार किसी भी एकल ईट का Compressive strength 85kg/cm^2 से कम नहीं होना चाहिए। जबकि चार ईट के नमूने में दो ईट का Compressive strength 85 kg/cm से कम है। ईट के अन्य पारामीटर भी विशिष्ट के अनुरूप नहीं हैं।

उक्त के आलोक में श्री माखन लाल गुप्ता, तत० सहायक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक-02, दिनांक 19.7.2016 द्वारा द्वितीयकारण पृच्छा का जवाब विभाग में समर्पित किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी हैं :-

- (i) Is Code-5454 के कंडिका-3 में ईट की जाँच का method of sampling वर्णित है। जो निम्नवत है।
 - (a) 3.2.1 में Sampling in motion.
 - (b) 3.2.2 में Sampling from a stock
 - (c) 3.2.3 में Sampling from lorries or truck इस तरह कार्य में व्यवहृत होने के पूर्व ही नये ईटों की Sampling करनी थी। उड़नदस्ता द्वारा निर्धारित Sampling की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। संभवतः इसी कारण से उड़नदस्ता द्वारा चारों ईटों का औसत Compressive strength निकाल कर 100kg/cm^2 से तुलना की गयी है एवं ईट के निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि इन ईटों का मानक के नजदीक माना जाय।
- (ii) Stock से नई ईट नहीं लेने एवं लेईंग को तोड़कर ईट लेने एवं उससे compressive strength तथा अन्य भौतिक गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या मैंने संचालन पदाधिकारी को स्पष्ट करते हुए बचाव-बयान में लिखित रूप से दिया गया था। जिसे समीक्षा में नजर अंदाज कर दिया गया।
- (iii) संचालन पदाधिकारी द्वारा भी उक्त कंडिका (ii) में उठायी गयी तथ्यों का विस्तार से विवेचना करते हुए अंकित किया गया है कि यह निदेश उन ईटों पर लागू होता है जिसकी जाँच व्यवहार से पूर्व ही किया गया है।
- (iv) संचालन पदाधिकारी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुराने तोड़कर निकाले गये ईटों की तुलना नई ईटों के गुण धर्म से करना उचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में चूंकि ईट की Sampling is code 5454 के अनुरूप नहीं की गयी है। इसलिए ईट का औसत compressive strength $\text{tks } 86.00\text{kg/cm}^2$ है को एकल ईट का अनुमान्य compressive strength 85kg/cm^2 से अधिक पाये के फलस्वरूप ईटों का मानक के अन्तर्गत माना गया।

श्री गुप्ता, तत० सहायक अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। जिसमें निम्न तथ्य पाये गये हैं :-

श्री गुप्ता, तत० सहायक अभियंता द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बचाव-बयान के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा Is code 5454 के कंडिका 5.2.1.1 का उल्लेख करते हुए जाँच में पाये ईटों का औसत compressive strength 85kg/cm^2 अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत बताते हुए आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया था। उल्लेखनीय है कि is code 5454 की कंडिका 5.2.1.1 के अनुसार किसी भी एकल ईट का compressive strength 85.00kg/cm^2 से कम नहीं होना चाहिए। जाँच में चार अदद ईट (एकत्रित) के नमूनों का compressive strength 95.68, 94.18, 75.34 एवं $74-48\text{kg/cm}^2$ पाया गया एवं प्रथम श्रेणी के ईट का औसत compressive strength 100kg/cm^2 होता है। उक्त से स्पष्ट है कि जाँचित चार अदद ईट के नमूनों में से अदद ईट का compressive strength 85kg/cm^2 से कम पाया गया है।

श्री गुप्ता, तत० सहायक अभियंता द्वारा Is code-5454 के कंडिका-3.2.1, 3.2.2 एवं 3.2.3 में Methods of sampling का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि is code के अनुसार कार्य में प्रयुक्त होने के पूर्व ही नये ईटों की

Sampling करने का प्रावधान है। जबकि उड़नदस्ता द्वारा कराये गये Laying कार्य में से छेनी हथौड़ी से तोड़कर ईंट का नमूना संग्रह कर जाँच करायी गयी है जो IS code के निर्धारित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। उक्त कोड में व्यवहृत ईंट की Sampling करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप जाँच में पाये गये चारों ईंट का औसत compressive strength 86.00kg/cm^2 मान्य सीमा के अन्तर्गत है।

प्रश्न है जब is code 5454 के कंडिका— 3.2.1, 3.2.2 एवं 3.2.3 कार्य में व्यवहृत ईंट के नमूनों पर लागू नहीं होता है तो फिर उसी कोड के कंडिका 5.2.1.1 के संदर्भ में ईंट का compressive strength की मान्य सीमा 85kg/cm^2 के आधार पर मान्यता दिया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में 1004 ईंट का औसत compressive strength 100kg/cm^2 के जगह पर चारों ईंट का औसत compressive strength 86kg/cm^2 पाया जाना परिलक्षित करता है कि कार्य में न्यून विशिष्टि को ईंट का उपयोग किया गया है साथ ही ईंट की नमूनों की जाँच में अन्य पारामीटर यथा under burnt, face disorted, or rounded shape पाया गया है। जबकि भुगतान प्रावधान के अनुरूप किया गया है।

अतः न्यून विशिष्टि के ईंट का उपयोग करने तथा प्रावधान के अनुरूप अनियमित भुगतान करने के लिए श्री माखन लाल गुप्ता, तत0 सहायक अभियंता दोषी पाये गये हैं।

अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री माखन लाल गुप्ता, तत0 सहायक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल सं0—1, मुजफ्फरपुर में निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

“दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक”

उक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

अतः उक्त आदेश श्री माखन लाल गुप्ता, तत0 सहायक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल सं0—1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, लालगंज, वैशाली को अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

“दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक”

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।

20 अप्रैल 2017

सं० 22/नि0सि0(मुज0)—06—10/2012—561—श्री राम विनोद सिंह (आई०डी०—2101) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरुद्ध उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान वर्ष 2012 में मलिकपुर शाखा नहर के वि०दू० 56.00 पर कराये जा रहे कैनाल लाईनिंग कार्यों में बरती गयी अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल, पटना द्वारा की गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक—657, दिनांक 11.06.2013 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०—1830, दिनांक 04.12.14 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही दिनांक 31.01.2016 को श्री सिंह के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं०—21 सहज्ञापांक 424, दिनांक 10.3.16 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में सम्मिश्रित किया गया है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए ब्रिक लाईनिंग कार्य में व्यवहृत प्लास्टर में सीमेंट की मात्रा में कमी के आरोप को अप्रमाणित एवं असहमत होते हुए कैनाल लाईनिंग कार्य में व्यवहृत ईंट के Compressive strength 70.72kg/cm^2 पाये जाने के आरोप को प्रमाणित पाया गया तथा असहमति के निम्न बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 1070, दिनांक 10.6.16 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

- (1) Is code -5454 की कंडिका 5.2.1.1 के अनुसार नमूने के किसी भी ईंट का compressive strength 85kg/cm^2 से कम नहीं होना चाहिए। जबकि आलोच्य कार्य के नमूने के सभी पाँच ईंटों का compressive strength 85kg/cm^2 से कम है। ईंट के अन्य पारामीटर भी विशिष्टि के अनुरूप नहीं है।

उक्त के आलोक में श्री सिंह, तत0 कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक—01, दिनांक 16.8.2016 द्वारा द्वितीयकारण पृच्छा का जवाब विभाग में समर्पित किया। जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी हैं।

- (i) Is Code-5454 में प्रावधान है कि compressive strength of any individual brick tested in the sample shall not below the minimum average compressive strength for the corresponding class of brick more than 15% उक्त के आलोक में द्वितीय कारण पृच्छा के बिन्दु में अंकित होना कि 85kg/cm^2 से किसी ब्रीक का compressive strength कम नहीं होने का उल्लेख भ्रामक एवं साक्ष्य समर्थित तथ्य पर आधारित नहीं है।

- (ख) IS कोड कंडिकाओं 3.2.1, 3.2.2 एवं 3.2.3 में क्रमशः sampling in motion, sampling from stack, or sampling from lorries of truck का उल्लेख है। इसमें कहीं भी कार्य में व्यवहृत ईंट

(वह भी मोटर में बैठाया हुआ एवं उस पर प्लास्टर किया हुआ) से निर्मित लेयर को काटकर नमूना एकत्र कर compressive strength की जाँच प्रतिवेदन में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि ईंट के नमूने IS कोड 5454 के प्रावधान के आलोक में एकत्र नहीं किया गया है। फलतः IRI द्वारा प्रतिवेदित जाँचफल प्रावैधिक दृष्टिकोण से प्रमाणित विश्वसनीय एवं भरोसेमंद नहीं है।

- (ग) लेईंग कार्य हेतु ब्रीक टाइल्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होने के कारण विशिष्टि में परिवर्तन कर ब्रीक का प्रावधान की स्वीकृति दी गयी थी। लेकिन विशिष्टि परिवर्तन में ईंट के ग्रेड एवं compressive strength का कोई जिक्र नहीं है। ईंट का अपेक्षित compressive strength की परिकल्पना कर उसे 100A ब्रिक मानकर गलत तरीके से ईंट का नमूना एकत्रित कर compressive strength की तुलना करने का विधि सम्मत आधार नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रीक टाइल्स के अपेक्षित compressive strength का आकलन किया गया जो 66.67 kg/cm^2 compressive strength आकलित है। उसी आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा स्थापित किया गया कि तकनीकी रूप से व्यवहृत ईंट का compressive strength 66.67 kg/cm^2 अपेक्षित है। जिसके अनुसार जाँचित पाँचों ईंटों का compressive strength 70.22 kg/cm^2 पाया गया है जो आकलित $62-67 \text{ kg/cm}^2$ से लगभग 6% अधिक है।

श्री सिंह, तत0 कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी जिसमें निम्न तथ्य पाये गये :-

उड़नदस्ता जाँच में कार्य स्थल से एकत्रित पाँच अदद ईंट के नमूनों की जाँच में compressive strength 66.79, 79.32, 82.62, 59.49 , ,oa 69.40 kg/cm^2 पाया गया है। साथ ही ईंट का water absorption 21.47 (मानक 20 प्रतिशत से अधिक) Colour Non Uniform, Under Burnt, Shape Distorted, Edge Rounded एवं Sound dull पाया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि कार्य में उपयोग किये गये ईंट विशिष्टि के अनुरूप नहीं है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा IS code 5454 की कंडिका 5.2.1.1 तथा मूल प्राक्कलन में प्रावधानित ब्रीक टाइल्स का compressive strength का आकलन 66.67 kg/cm^2 ही रहना चाहिए। जबकि जाँच में औसत compressive strength 70.72 kg/cm^2 पाया गया है तथा ईंट को खोदकर निकालने के क्रम में भी स्ट्रेन्थ पर प्रभाव पड होगा एवं अन्य पारामीटर यथा रंगरूप में कमी आना स्वभाविक है के आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं होने का मतव्य दिया गया है।

श्री सिंह सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता द्वारा IS code 5454 के कंडिका 3.2.1, 3.2.2 एवं 3.2.3 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इस कंडिका के अनुसार नये ईंट का सैंपलिंग किया जाना है जबकि उड़नदस्ता द्वारा कराये गये कार्यों में व्यवहृत ईंट को निकालकर नमूना एकत्रित किया गया है। कार्य में व्यवहृत ईंट के सैंपलिंग करने का इस कोड में कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्न है जब IS code 5454 के कंडिका 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 कार्य में व्यवहृत ईंट पर लागू नहीं होता है तो कंडिका 5.2.1.1 के आलोक में ईंट के compressive strength 80.00 kg/cm^2 से कार्य में व्यवहृत ईंट की जाँच में पाये गये compressive strength की तुलना किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

श्री सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता द्वारा यह भी कहा गया है कि मूल प्राक्कलन में लाईनिंग कार्य ब्रीक टाइल्स से करने का प्रावधान था परंतु ब्रीक टाइल्स उपलब्ध नहीं होने के कारण conventional brick से कार्य कराने की अनुमति दी गयी परंतु 100A ब्रीक के specification की बाध्यता नहीं रखी गयी जबकि लाईनिंग कार्य में 100A brick का उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में उच्च पदाधिकारी से विचार विमर्श कर यथोचित कार्रवाई करना चाहिए था जो मो0 आलम द्वारा नहीं किया गया है।

श्री सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता द्वारा brick tiles dk compressive strength $66-67 \text{ kg/cm}^2$ का आकलन करते हुए कहा गया है कि तकनीकी रूप से ब्रीक का compressive strength 66.67 kg/cm^2 होने पर मान्य सीमा के अन्तर्गत माना जा सकता है जबकि उड़नदस्ता जाँच में औसत ईंट का compressive strength 70.72 kg/cm^2 पाया गया है, को स्वीकार योग्य नहीं माना गया है। क्योंकि नहर में लाईनिंग कार्य 100A brick से किया जाता है जिसका औसत compressive strength 100 kg/cm^2 होना है जाँच में ईंट के अन्य पारामीटर भी विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया है एवं जिसके लिए श्री सिंह दोषी हैं।

अतएव उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राम विनोद सिंह, तत0 कार्यपालक अभियंता तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

“पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती तीन वर्षों के लिए”।

उक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

अतः उक्त आदेश श्री राम विनोद सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, शिवशंकर पथ, क्लब रोड, मीठनपुरा, पो0-रमना, जिला-मुजफ्फरपुर को अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।
"पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती तीन वर्षों के लिए"।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।

21 अप्रैल 2017

सं० 22/नि0सि0(मुज0)-06-10/2012-582—श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह (आई०डी०-2282) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरुद्ध उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान वर्ष 2012 में तिरहुत मुख्य नहर के वि०दू० 679.50 पर कराये जा रहे कैनाल लाईनिंग कार्यों में बरती गयी अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल, पटना द्वारा की गयी। उड़नदस्ता अंचल, पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-658, दिनांक 11.06.2013 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं०-1831, दिनांक 04.12.14 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के निम्न बिन्दुओं पर श्री सिंह से विभागीय पत्रांक-1073, दिनांक 10.6.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

(1) Is code -5454 के अनुसार किसी भी एकल ईट का Compressive strength 85kg/cm^2 से कम नहीं होना चाहिए। जबकि चार ईट के नमूने में दो ईट का Compressive strength 85 kg/cm से कम है। ईट के अन्य पारामीटर भी विशिष्टि के अनुरूप नहीं है।

उक्त के आलोक में श्री सिंह सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक-0, दिनांक 21.7.2016 द्वारा द्वितीयकारण पृच्छा का जवाब विभाग में समर्पित किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गयी हैं :-

- (i) Is Code-5454 के कंडिका-3 में ईट की जाँच का method of sampling वर्णित है। जो निम्नवत है।
 - (a) 3.2.1 में Sampling in motion.
 - (b) 3.2.2 में Sampling from a stock
 - (c) 3.2.3 में Sampling from lorries or truck इस तरह कार्य में व्यवहृत होने के पूर्व ही नये ईटों की Sampling करनी थी। उड़नदस्ता द्वारा निर्धारित Sampling की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। संभवतः इसी कारण से उड़नदस्ता द्वारा चारों ईटों का औसत Compressive strength निकाल कर 100kg/cm^2 से तुलना की गयी है एवं ईट के निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि इन ईटों का मानक के नजदीक माना जाय।
- (ii) Stock से नई ईट नहीं लेने एवं लेईंग को तोड़कर ईट लेने एवं उससे compressive strength तथा अन्य भौतिक गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या मैंने संचालन पदाधिकारी को स्पष्ट करते हुए बचाव-बयान में लिखित रूप से दिया गया था। जिसे समीक्षा में नजर अंदाज कर दिया गया।
- (iii) संचालन पदाधिकारी द्वारा भी उक्त कंडिका (ii) में उठायी गयी तथ्यों का विस्तार से विवेचना करते हुए अंकित किया गया है कि यह निदेश उन ईटों पर लागू होता है जिसकी जाँच व्यवहार से पूर्व ही किया गया है।
- (iv) संचालन पदाधिकारी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुराने तोड़कर निकाले गये ईटों की तुलना नई ईटों के गुण धर्म से करना उचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में चूंकि ईट की Sampling is code 5454 के अनुरूप नहीं की गयी है। इसलिए ईट का औसत compressive strength $\text{tks } 86.00\text{kg/cm}^2$ है को एकल ईट का अनुमान्य compressive strength 85kg/cm^2 से अधिक पाये के फलस्वरूप ईटों का मानक के अन्तर्गत माना गया।

श्री सिंह, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। जिसमें निम्न तथ्य पाये गये हैं :-

श्री सिंह, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बचाव-बयान के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा Is code 5454 के कंडिका 5.2.1.1 का उल्लेख करते हुए जाँच में पाये ईटों का औसत compressive strength 85kg/cm^2 अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत बताते हुए आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया था। उल्लेखनीय है कि is code 5454 की कंडिका 5.2.1.1 के अनुसार किसी भी एकल ईट का compressive strength 85.00kg/cm^2 से कम नहीं होना चाहिए। जाँच में चार अदद ईट (एकत्रित) के नमूनों का compressive strength 95.68, 94.18, 75.34, 74.48 kg/cm^2 पाया गया एवं प्रथम श्रेणी के ईट का औसत compressive strength 100kg/cm^2 होता

है। उक्त से स्पष्ट है कि जाँचित चार अद्द ईट के नमूनों में से अद्द ईट का compressive strength 85kg/cm^2 से कम पाया गया है।

श्री सिंह, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता द्वारा Is code-5454 के कडिका-3.2.1, 3.2.2 एवं 3.2.3 में Methods of sampling का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि IS code के अनुसार कार्य में प्रयुक्त होने के पूर्व ही नये ईंटों की Sampling करने का प्रावधान है। जबकि उड़नदस्ता द्वारा कराये गये Laying कार्य में से छेनी हथौड़ी से तोड़कर ईट का नमूना संग्रह कर जाँच करायी गयी है जो IS code के निर्धारित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। उक्त कोड में व्यवहृत ईट की Sampling करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप जाँच में पाये गये चारों ईट का औसत compressive strength 86.00kg/cm^2 मान्य सीमा के अन्तर्गत है।

प्रश्न है जब is code 5454 के कडिका- 3.2.1, 3.2.2 एवं 3.2.3 कार्य में व्यवहृत ईट के नमूनों पर लागू नहीं होता है तो फिर उसी कोड के कडिका 5.2.1.1 के संदर्भ में ईट का compressive strength की मान्य सीमा 85kg/cm^2 के आधार पर मान्यता दिया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में 1004 ईट का औसत compressive strength 100kg/cm^2 के जगह पर चारों ईट का औसत compressive strength 86kg/cm^2 पाया जाना परिलक्षित करता है कि कार्य में न्यून विशिष्टि को ईट का उपयोग किया गया है साथ ही ईट की नमूनों की जाँच में अन्य पारामीटर यथा under burnt, face disorted, rounded shape पाया गया है। जबकि भुगतान प्रावधान के अनुरूप किया गया है।

अतः न्यून विशिष्टि के ईट का उपयोग करने तथा प्रावधान के अनुरूप अनियमित भुगतान करने के लिए श्री सिंह दोषी पाये गये हैं।

अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल सं०-1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त में निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

“पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती तीन वर्षों के लिए”

उक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

अतः उक्त आदेश श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, C/o कविन्द्र प्रसाद सिंह, कन्या उच्च विद्यालय के निकट दामूचक रोड, मुजफ्फरपुर को अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

“पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती तीन वर्षों के लिए”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।

26 अप्रील 2017

सं० 22/नि०सि०(पू०)-01-07/2016-609—मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, कटिहार के परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया के अधीन एजेण्डा सं०-133/201 एवं 133/202 के तहत कोशी नदी के दाँये तट पर क्रमशः सहोरा एवं मदरौनी स्थल पर वर्ष 2016 बाढ़ के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य में बरती गयी अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता द्वारा की गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री ज्ञान प्रकाश लाल, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर से निम्नांकित आरोपों के लिए प्रपत्र-‘क’ के साथ स्पष्टीकरण किया गया :-

- (1) कोशी नदी के दाँये तटबंध पर स्थित मदरौनी ग्राम के समीप बाढ़ वर्ष 2016 के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य के डाउन स्ट्रीम में 300 मी० विस्तारित भाग में बोल्टर रिमेंट कराने का सुझाव अध्यक्ष विशेष जाँच दल द्वारा दिनांक 24.04.16 को दी गई। तत्संबंधी प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लेते हुए विलंब से वांछित प्रस्ताव मुख्य अभियंता, भागलपुर के पत्रांक 1197, दिनांक 11.05.16 से दिनांक 12.05.16 को विभाग को प्राप्त करायी गई जिसकी स्वीकृति विभागीय पत्रांक 1764, दिनांक 26.05.16 से दी गई एवं विस्तारित भाग में दिनांक 02.06.16 को विलंब से कार्य प्रारंभ कराया गया। तब तक नदी का जल स्तर न्यूनतम जल स्तर (LWL) से अधिक हो चुका था। जो स्कोप ऑफ वर्क में बदलाव का कारण बना तथा कराये गये कार्य क्षतिग्रस्त होने तथा ससमय कार्य पूरा नहीं होने का कारक बना। जबकि दिनांक 31.05.16 तक आप मुख्य अभियंता, भागलपुर के प्रभार में रहे हैं। इससे परिलक्षित होता है कि आप नदी में जल स्तर बढ़ने पर कार्य प्रारंभ कराने का इंतजार कर रहे थे ताकि जैसे-तैसे कार्य करा कर सरकारी राशि का गबन हो सके। इस प्रकार विस्तारित कार्य का प्रभाव विभाग में विलंब से समर्पित करने एवं स्वीकृति के उपरांत विलंब से कार्य प्रारंभ करने के कारण कराये गये कार्य का क्षतिग्रस्त होना परिलक्षित करता है कि आपके द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है तथा अधिनस्थ पदाधिकारी पर प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव रहा है, जिसके लिये आप दोषी हैं।

- (2) सहोरा एवं मदरौनी स्थल पर कराये गये कटाव निरोधक कार्य की जाँच में बोल्टर क्रेटिंग कार्य में Voids मानक से अधिक पाया गया। बोल्टर का वजन, G.I. Wire Crate का मेश का आकार मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। साथ ही Boulder Crating कार्य में प्रावधान के अनुरूप G.I. binding wire का उपयोग नहीं पाया गया। इस प्रकार प्राक्कलन/एकरारनामा में निहित

विशिष्टि से न्यून विशिष्टि का कार्य होना परिलक्षित करता है कि आपके द्वारा स्थल निरीक्षण एवं कार्यों के पर्यवेक्षण में पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है जिसके लिये आप दोषी हैं।

श्री ज्ञान प्रकाश लाल से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी, समीक्षा में पाया गया कि श्री लाल के विरुद्ध मुख्य आरोप के बिन्दु निम्न हैं :-

आरोप 1 :-

- (क) अध्यक्ष अनुवीक्षण दल द्वारा दिनांक 24.04.16 को विस्तारीकरण कार्य हेतु दिये गये सुझाव को गंभीरता से नहीं लेते हुए वांछित प्रस्ताव विलंब से समर्पित करना।
- (ख) विभाग द्वारा दिनांक 26.05.16 को विस्तारिकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने के बाद विलंब से दिनांक 02.06.16 को कार्य प्रारंभ होने के कारण न्यूनतम जलस्तर से उपर कार्य कराना पड़ा एवं स्कोप ऑफ वर्क में बदलाव करना पड़ा। फलतः विस्तारित कार्य क्षतिग्रस्त हो गया। जो आपका पदीय दायित्वों में लापरवाही एवं प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव दर्शाता है।

प्रभार प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री लाल दिनांक 30.04.16 को श्री विनोद कुमार गुप्ता से सिंचाई अंचल, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किये हैं एवं विभाग के पुर्नगठन के क्रम में दिनांक 21.05.16 तक उक्त अंचल के प्रभार में रहे हैं।

आरोपी द्वारा अपने स्पष्टीकरण के कंडिका 1 से 5 तक में दिनांक 29.04.16 तक मुख्य अभियंता, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा विस्तारित कार्य के संदर्भ में की गयी कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। चूँकि इनके द्वारा दिनांक 30.04.16 को सिंचाई अंचल भागलपुर का कार्यभार ग्रहण किया है ऐसी स्थिति दिनांक 30.04.16 के बाद इनके द्वारा विस्तारित कार्य के संदर्भ में कृत्य कार्रवाई की समीक्षा किया जाना समाचीन प्रतीत होता है।

इनके द्वारा कहा गया है कि दिनांक 05.05.16 को मदरौनी एवं सहोरा कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया तथा मदरौनी गाँव के D/s में 200 मी० में अतिरिक्त लंबाई में कार्य कराने की आवश्यकता महसूस किया गया। कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-520, दिनांक 04.05.16 जो अंचल कार्यालय में दिनांक 06.05.16 को प्राप्त हुआ के आलोक में उड़नदस्ता टीम द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में विस्तारित कार्य की स्वीकृति हेतु पत्रांक-512, दिनांक 05.04.16 से मुख्य अभियंता को प्रस्ताव समर्पित किया गया। इस प्रकार माना जा सकता है कि दिनांक 24.04.16 से 05.09.16 तक प्रमंडल स्तर पर प्रस्ताव के समर्पण में विलंब हुआ।

उक्त प्रस्ताव को मुख्य अभियंता द्वारा पत्रांक-1197, दिनांक 11.5.16 से दिनांक 12.05.16 को विभाग में समर्पित किया गया है। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 1764, दिनांक 26.05.16 से मूल कार्य के अनुरूप में ही विस्तारित कार्य की स्वीकृति संसूचित की गयी। उक्त स्वीकृत्यादेश पत्र की प्रति मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 26.05.16 को कार्यपालक अभियंता को प्राप्त कराया गया है। पुनः मुख्य अभियंता ने अपने पत्रांक 1364, दिनांक 28.05.16 से दिन रात कार्य करा कर शीघ्र पुरा करने का निदेश दिया एवं विस्तारित कार्य का प्राक्कलन की मांग की गयी। मुख्य अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता के साथ दिनांक 31.05.16 को किये गये स्थल निरीक्षण का निरीक्षण प्रतिवेदन जो उनके पत्रांक 1393, दिनांक 21.05.16 से विभाग एवं अधीनस्थ पदाधिकारी को दी गयी है के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 31.05.16 को विस्तारित भाग में एप्रोन में मिट्टी कार्य कराने के पश्चात GTF Laying का कार्य किया गया था एवं बोल्टर क्रेटिंग कार्य 30-40 मजदूरों द्वारा किया जा रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि विस्तारित भाग में मिट्टी का कार्य 29.05.16/30.5.16 को प्रारंभ किया गया है। आरोपी द्वारा भी कहा गया है कि दिनांक 29.05.16 से कार्य प्रारंभ किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश के पश्चात मात्र 3 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ होना परिलक्षित होता है। 3 दिन का विलंब भी संवेदक एवं कार्यपालक अभियंता के कारण परिलक्षित होता है। अतएव स्वीकृत्यादेश के पश्चात जान बूझकर जल स्तर बढ़ने का इंतजार कर रहे थे एवं कार्य विलंब से प्रारंभ कराये जाने के लिए श्री लाल को दोषी माना जाना समाचीन प्रतीत नहीं होता है।

श्री लाल दिनांक 31.05.16 से उक्त सरकार से मुक्त हो चुके थे ऐसी स्थिति में समय पर बाढ़ 2016 के पूर्व कार्य नहीं कराने के लिए दोषी नहीं माना जा सकता। जहाँ तक कार्य के स्वरूप में बदलाव कर कार्य कराने का प्रश्न है तो स्थल पंजी से स्पष्ट होता है कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 08.06.16 को स्थल पंजी पर उद्धित किया है कि स्वीकृत स्कोप ऑफ वर्क में 12m x 1.8m बोल्टर का एप्रोन बनाना है परंतु 120मी० के D/s में मिट्टी काटकर 12मी० का एप्रोन बनाना उचित नहीं है। यह नोज नदी की धारा को स्पर तरफ डिफेक्ट करता है अतः Reseted available width में NC base के उपर 6m x 3.6m का एप्रोन एजे क्रेटिंग बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। परंतु अधीक्षण अभियंता अपने अनुशंसा में कहा है कि नदी के जल स्तर बढ़ जाने के कारण 12मी० चौड़ाई में एप्रोन बनाने में हो रहे व्यवहारिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए कार्यपालक अभियंता का प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा दिनांक 08.06.16 को ही स्थल पंजी में दी गयी है। इससे स्पष्ट है कि श्री लाल का कार्य के स्वरूप के बदलाव में कोई सहभागिता नहीं रही है।

आरोप 2 :-

आरोप का मुख्य अंश है कि उड़नदस्ता जाँच में बोल्टर क्रेटिंग कार्य में voids मानक से अधिक पाया गया तथा बोल्टर का वजन GI wire Crate का मेश साईज तथा GI winding wire का उपयोग मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है इस प्रकार प्राक्कलन एवं विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं होना परिलक्षित करता है कि आपके द्वारा स्थल निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में पदीय दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है।

आरोपी द्वारा मुख्य अभियंता के पत्रांक 1065, दिनांक 02.05.16 की प्रति संलग्न करते हुए कहा गया है कि दिनांक 02.05.16 तक सहोरा एवं मदरौनी स्थल पर क्रमशः 78 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत प्रगति हो चुकी थी यह भी कहा गया है कि दिनांक 05.05.16 का अध्यक्ष विशेष जाँच दल का निरीक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि एप्रोन का कार्य पूर्ण हो चुका था एवं स्लोप में बोल्टर पीचिंग का कार्य प्रगति में था। इससे स्पष्ट है कि स्लोप में बोल्टर क्रेटिंग एवं पीचिंग का कार्य दिनांक 30.4.16 के बाद दिनांक 15.05.16 तक कराया गया है उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उड़नदस्ता द्वारा दोनों स्थलों पर स्लोप में बोल्टर पीचिंग/क्रेटिंग का जाँच किया गया है। आरोपी द्वारा कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में कहा गया है कि कार्य के दौरान उड़नदस्ता/अनुवीक्षण दल एवं शोध प्रमंडल द्वारा स्थल निरीक्षणोपरांत दिये गये प्रतिवेदन में कार्य संतोषप्रद बताया गया है एवं गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ये सभी प्रतिवेदन दिनांक 23.4.16 के पूर्व का है। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उड़नदस्ता द्वारा कार्य के दौरान दिनांक 29.02.16 एवं 28.03.16 को स्थल निरीक्षण किया गया है, इन दोनों जाँच दल के प्रतिवेदन के आधार पर यह स्थापित किया जाना कि दिनांक 31.05.16 के बाद स्लोप में बोल्टर क्रेटिंग कार्य प्रावधान के अनुरूप किया गया है उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ एक भी निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया है न ही विशिष्ट के अनुरूप कार्य कराने हेतु अधीनस्थ पदाधिकारी को दिये गये निदेश से संबंधित कोई अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया है। अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माना जा सकता है कि श्री लाल द्वारा स्थल निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य में पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है। जिसके लिये श्री लाल दोषी है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री ज्ञान प्रकाश लाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर को "दो वेतन वृद्धि पर असंचात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री ज्ञान प्रकाश लाल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :-

"दो वेतन वृद्धि पर असंचात्मक प्रभाव से रोक"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।

26 अप्रिल 2017

सं० 22/नि०सि०(पू०)-01-07/2016-610—मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर वर्तमान में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, कटिहार के परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया के अन्तर्गत एजेण्डा सं०-133/201 एवं 133/202 के तहत बाढ़ वर्ष 2016 के पूर्व कोशी नदी के दाँये तट पर क्रमशः सहोरा एवं मदरौनी स्थल पर कराये गये कटाव निरोधक कार्य में बरती गयी अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता द्वारा की गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत निम्नांकित आरोपों के लिए श्री सियाराम पासवान, तत्कालीन मुख्य अभियंता, कटिहार के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र-क के साथ स्पष्टीकरण किया गया :-

- (1) सहोरा एवं मदरौनी ग्राम के निकट बाढ़ वर्ष 2016 के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य के विस्तारित कार्य का दिनांक 26.05.16 को विभागीय स्वीकृति संसूचित होने के बावजूद नदी के जल स्तर बढ़ने के बाद न्यूनतम जल स्तर (LWL) से उपर विलंब से दिनांक 02.06.16 को कार्य प्रारंभ कराया गया। जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 3.00 से विस्तारित कार्य कई बिन्दुओं पर क्षतिग्रस्त पाया गया जिससे न्यून विशिष्टि का कार्य कराया जाना एवं जाँच तिथि तक पूर्ण नहीं होना परिलक्षित करता है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा स्थल निरीक्षण एवं कार्यों के पर्यवेक्षण में पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है, जिसके लिए आप दोषी है।

श्री पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि -

आरोपी द्वारा कहा गया है कि वे दिनांक 01.06.16 को मुख्य अभियंता, कटिहार का प्रभार ग्रहण किया गया है तथा दिनांक 01.06.16 से ही आलोच्य कार्य इस परिक्षेत्र का हिस्सा बना है जिसे स्वीकार योग्य माना जा सकता है।

आरोपी द्वारा कहा गया है कि दिनांक 03.06.16 को दोनों कार्यस्थल का किये गये स्थल निरीक्षण में बोल्टर क्रेटिंग कार्य द्रुत गति से चल रहा था एवं स्थल पर बोल्टर की उपलब्धता देखा गया था तथा कार्य को विशिष्टि एवं गुणवत्ता के अनुरूप एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। जिसकी पुष्टि निरीक्षण प्रतिवेदन से होती है।

श्री पासवान द्वारा स्कोप ऑफ वर्क में बदलाव किये जाने के संदर्भ में कहा गया है कि दिनांक 10.6.16 को स्थल निरीक्षण में स्थल स्थिति के अनुरूप विस्तारित कार्य 200 मी० में से 120मी० के D/s में 80मी० में 12मी० X 1.8 मी० के एप्रोन के बदले 6मी० X 3.6मी० का एप्रोन बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ताकि नदी की धारा इस बिन्दु से मुड़कर बायें किनारे की तरफ चली जाय। यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि रिमेंटमेंट कार्य में नदी की धारा में किसी प्रकार की abstraction होने पर उसके D/s में Rolling Water Effect उत्पन्न होना स्वभाविक है जो रिमेंटमेंट क्षतिग्रस्त होने का कारण बन सकता है।

आरोपी द्वारा Hand book for antierrosion flood protection and river training work के Page-43 कंडिका 4.6 में Design of Bank Revetment के आधार पर कहा गया है कि स्कोप ऑफ वर्क में बदलाव नहीं किया गया है एवं कहा गया है कि

उक्त कंडिका के अनुसार In case of limitation of space width of lanching apron may be reduced and thickness is increased keeping the volume per m. length remain same.

प्रस्तुत मामले में मूल कार्य में स्कोप ऑफ वर्क में 12m x 1.8m apron में प्रावधानित per meter बोल्टर की मात्रा 21.6M3 के बराबर ही 6m x 3.6m (21.6M3) कार्य में लगाया गया है तथा लोड ऑफ बोल्टर क्रेटिंग 6मी० x 3.6मी० की गणना की गयी है उक्त गणना के अनुसार Load/M2=4.25T/M2 बताया गया है। जो 10.75 T/M2 से कम होने के आधार पर सेफ बताया गया है। उक्त तथ्यों को साक्ष्य के आलोक में स्वीकार योग्य माना जा सकता है परंतु विभागीय द्वारा स्वीकृत स्कोप ऑफ वर्क में बिना विभागीय अनुमति एवं वस्तुस्थिति की जानकारी विभाग को दिये बिना ही कार्य के स्वरूप में बदलाव करने को उचित नहीं माना जा सकता है। विस्तारित कार्य क्षतिग्रस्त होने के संदर्भ में कहा गया है कि दिनांक 23.06.16 के 60 मी० में बनाया गया Lanching apron, launch कर गया। उसके बाद उस बिन्दु पर कटाव नहीं हुआ। एप्रोन Launch करने के लिए बनाया जाता है। अतः इसे क्षतिग्रस्त होना या न्यून विशिष्टि के होने के कारण क्षतिग्रस्त होना किसी दृष्टि से सही नहीं है जबकि उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन 3.0.0(iii) के अंतिम कंडिका में स्पष्ट रूप से अंकित है कि एप्रोन के साथ-साथ स्लोप पिचिंग क्षतिग्रस्त पाया गया है। जिस पर अभियंता प्रमुख (उत्तर) की उपस्थिति में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। तथा उड़नदस्ता कंडिका 4.0.0(v) में विस्तारित भाग में विलंब से कार्य प्रारंभ करने, स्कोप ऑफ वर्क के बदलाव करने तथा कार्य पुरा नहीं होने के लिए कनीय अभियंता से मुख्य अभियंता को जिम्मेवार माना गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य के स्वरूप में बिना विभागीय अनुमति प्राप्त किये ही कार्य के स्वरूप में बदलाव करने के लिये इन्हें जिम्मेवार माना जा सकता है।

आरोपी द्वारा समय पर विस्तारित कार्य पूर्ण नहीं होने के संदर्भ में कहा गया है कि 200मी० लंबाई में कार्य कराने हेतु बढ़ते जलस्तर की समस्या NH-80 से बोल्टर दुलाई में परेशानी को देखते हुए एक माह का समय दिया जाना उचित था। तथा यह भी कहा गया कि सहोरा स्थल पर विस्तारित 100मी० का कार्य 96.47 प्रतिशत दिनांक 16.06.16 तथा मदरौनी स्थल पर विस्तारित कार्य 100मी० का 91.47 प्रतिशत दिनांक 20.6.16 तक पूरा करा लिया गया था मात्र कुछ स्लोप पिचिंग एवं कैपिंग का कार्य कराना शेष था जिसे दिनांक 20.06.16 को NH-80 में कहलगाँव के पास पुल टूट जाने के फलस्वरूप दिनांक 23.12.16 को विभागीय बोल्टर काढ़ा गोला प्रमंडल से लेकर दिनांक 30.06.16 तक पूरा कराया गया। एक तरफ तो आरोपी द्वारा कहा जा रहा है कि दिनांक 30.6.16 को निरीक्षण में कार्य की प्रगति दूत गति से चल रहा था एवं स्थल पर बोल्टर की उपलब्धता पर्याप्त थी तथा दिनांक 10.6.16 को स्थल निरीक्षण में दिनांक 15.06.16 तक कार्य समाप्त करने का निदेश भी दिया गया है। दूसरे तरफ कहा जाना कि विस्तारित कार्य हेतु कम से कम 1 माह का समय होना चाहिये था। विरोधाभाष उत्पन्न करता है। इससे स्पष्ट होता है कि सही प्रबंधन नहीं किये जाने के कारण विस्तारित कार्य समय पर पूरा नहीं होना परिलक्षित होता है। जिसे आरोपी की विफलता मानी जा सकती है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री सियाराम पासवान, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, कटिहार को "दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री सियाराम पासवान, मुख्य अभियंता, कटिहार को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :-

"दो वेतन वृद्धि पर असंचात्मक प्रभाव से रोक"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।

26 अप्रैल 2017

सं० 22/नि०सि०(पू०)-01-07/2016-611—मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर वर्तमान में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, कटिहार के परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया के अन्तर्गत एजेण्डा सं०-133/201 एवं 133/202 के तहत बाढ़ वर्ष 2016 के पूर्व कोशी नदी के दाँये तट पर क्रमशः सहोरा एवं मदरौनी स्थल पर कराये गये कटाव निरोधक कार्य में बरती गयी अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता द्वारा की गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत निम्नांकित आरोपों के लिए श्री राजू कुमार सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, भागलपुर के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र-क के साथ स्पष्टीकरण किया गया :-

- (1) सहोरा एवं मदरौनी ग्राम के निकट बाढ़ वर्ष 2016 के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य के विस्तारित कार्य का दिनांक 26.05.16 को विभागीय स्वीकृति संसूचित होने के बावजूद नदी के जल स्तर बढ़ने के बाद न्यूनतम जल स्तर (LWL) से उपर विलंब से दिनांक 02.06.16 को कार्य प्रारंभ कराया गया। जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 3.00 से विस्तारित कार्य कई बिन्दुओं पर क्षतिग्रस्त पाया गया जिससे न्यून विशिष्टि का कार्य कराया जाना एवं जाँच तिथि तक पूर्ण नहीं होना परिलक्षित करता है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा स्थल निरीक्षण एवं कार्यों के पर्यवेक्षण में पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है, जिसके लिए आप दोषी है।

श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी समीक्षा में पाया गया कि श्री सिन्हा के विरुद्ध मुख्य आरोप निम्न हैं :-

अंश (क) :- विस्तारित कार्य का दिनांक 26.05.16 को विभागीय स्वीकृत्यादेश संसूचित होने के बावजूद नदी के जलस्तर पर बढ़ जाने के बाद LWL के उपर विलम्ब से दिनांक 02.06.16 को कार्य प्रारंभ किया जाना।

अंश (ख) :- विस्तारित कार्य कई बिन्दुओं पर क्षतिग्रस्त पाया गया जिससे न्यून विशिष्टि का कार्य कराया जाना एवं जाँच की तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं होना परिलक्षित करता है उक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा स्थल निरीक्षण कराने में एवं कार्यों के पर्यवेक्षण में पदीय दायित्व का निर्वहन किया गया है।

(i) अंश-क के संदर्भ में आरोपी द्वारा कहा गया है कि मेरे द्वारा अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 08.06.16 को कार्य प्रारंभ होने के बाद ग्रहण किया गया है। अतएव दिनांक 08.06.16 के पूर्व की जाने वाली कारवाई यथा दिनांक 26.05.16 को विभागीय स्वीकृत्यादेश के पश्चात विलम्ब से विस्तारित कार्य दिनांक 02.06.16 को प्रारंभ करने के लिये दोषी माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(ii) अंश-ख आरोप के इस अंश यथा विस्तारित कार्य न्यून विशिष्टि का कार्य कराने एवं समय पर पूरा नहीं होना तथा क्षतिग्रस्त होने के संदर्भ में आरोपी द्वारा कहा गया है कि

(i) उड़नदस्ता द्वारा विस्तारित कार्य की कोई जाँच नहीं की गयी है। अतएव एक अनुमान के आधार पर उक्त रीच में न्यून विशिष्टि का कार्य कराया गया है माना जाना उचित नहीं है। उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के कडिका 3.0.1 एवं 3.0.2, 3.0.3 एवं 3.0.4 से स्पष्ट होता है कि मूल कार्य के तहत मदरौनी एवं सहोरा स्थल पर कराये गये बोल्टर क्रेटिंग कार्य की जाँच की गयी है। अतएव आरोपी को मात्र संभावना के आधार पर न्यून विशिष्टि में बोल्टर क्रेटिंग कार्य कराने के लिए दोषी माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(ii) समय पर कार्य पूरा नहीं होने के संदर्भ में कहा गया है कि विभागीय पत्रांक-1764, दिनांक 26.05.16 में विस्तारित कार्य पूर्ण कराने हेतु विभाग द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी। आरोपी द्वारा यह कहा गया है कि मदरौनी स्थल पर मूल कार्य की लंबाई 600मी0 में रिभेटमेंट कराने हेतु कुल 96 दिन का समय एकरारनामा के अनुसार दिया गया था अर्थात् प्रति मी0 कार्य पूरा करने हेतु $600/96 = 6.25$ दिन का समय निर्धारित था। स्थल स्थिति के अनुसार विस्तारित कार्य कराने के लिये मूल एकरारनामा के अनुसार $240/6.25=38.4$ दिन की आवश्यकता थी जबकि विस्तारित कार्य दिनांक 30.06.16 अर्थात् 29 दिन में पूरा कराया गया है।

आरोपी द्वारा कार्य के प्रगति के संदर्भ में कहा गया है कि क्रेट रजिस्टर से स्पष्ट है कि दिनांक 02.06.16 से 08.06.16 के बीच कार्य की प्रगति धीमी थी तथा जिसका कारण बताया गया कि मूल एकरारनामा के कार्य दिनांक 15.05.16 को समाप्त होने के बाद संभवतः संवेदक द्वारा अपना Establishment हटा लिया गया हो तथा पुनः विस्तारित कार्य की प्रगति बढ़ाने में समय लगने से इंकार नहीं किया जा सकता है को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि मुख्य अभियंता, श्री सियाराम पासवान के दिनांक 03.06.16 के निरीक्षण प्रतिवेदन में कार्य दूत गति से होते हुए बताया गया है तथा स्थल बोल्टर की उपलब्धता भी देखा गया है।

आरोपी द्वारा यह भी कहा गया है कि NH-80 पर सवौर के पास NH-80 में पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण बोल्टर आपूर्ति बाधित होने के कारण दिनांक 23.06.16 को 300 घनमी0 विभागीय बोल्टर संवेदक को आपूर्ति कर दिनांक 30.06.16 तक पूरा कराया गया है। $416/90$ पर रक्षित संवेदक के पत्र से स्पष्ट होता है कि दिनांक 23.6.16 को 300 घनमी0 विभागीय बोल्टर संवेदक द्वारा माँग की गयी है। जिसे सम्भवतः आपूर्ति भी की गयी है। अतएव कार्य परिस्थितिजन विलंब से पुरा होना माना जा सकता है। परंतु इनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे परिलक्षित हो सके कि इनके द्वारा कार्य बाढ़ 2016 के पूर्व समाप्त करने हेतु कोई ठोस कारवाई की गयी हो। अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समय पर कार्य पूरा कराने के लिए समुचित प्रबंधन नहीं करने एवं पर्यवेक्षण के अभाव के लिये श्री सिन्हा दोषी पाये गये हैं।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री राजु कुमार सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर को दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजु कुमार सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, भागलपुर को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :-

“दो वेतन वृद्धि पर असंचात्मक प्रभाव से रोक”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।

5 मई 2017

सं० 22/नि०सि०(भाग०)—09—07/2010—641—श्री राजेश कुमार (आई०डी०—3472), तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर को वर्ष 2009—10 के उक्त पदस्थापन काल में रूपांकण प्रमंडल सं०—1, भागलपुर द्वारा वर्ष 2009 के बाढ़ अवधि में दिनांक 01.7.09 से 15.09.09 तक कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य को नियमानुसार विभाग के निबंधित संवेदकों से नामांकन के आधार पर नहीं कराकर विभागीय प्रक्रिया के विपरीत विभाग में अनिबंधित संवेदक से कराये जाने के आरोप के लिए प्रथम दृष्टव्या दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 771, दिनांक 11.7.12 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम— 19 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी श्री विवेक कुमार सिंह, अपर विभागीय जॉच आयुक्त—सह—प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग के पत्रांक—220, दिनांक 16.11.15 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होकर विभागीय प्रक्रिया अनिबंधित संवेदकों से संदर्भित बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराये जाने के प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर सम्प्रति अभियंता प्रमुख (उ०), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक 305, दिनांक 18.02.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

श्री राजेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर सम्प्रति अभियंता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—32, दिनांक 19.02.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया जिसमें निम्न तथ्यों को प्रस्तुत किया गया :—

- (i) अनिबंधित संवेदकों से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य दिनांक 01.07.09 को कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रारंभ कराया गया जिसकी सूचना 21 (इक्कीस) दिनों के पश्चात दिनांक 16.7.09 को इन्हें दी गयी जिसकी पूर्वानुमति कार्यपालक अभियंता द्वारा नहीं ली गयी।
- (ii) इनके द्वारा कार्य पर हुए व्यय से संबंधित पाक्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र—24 अनुशंसा के साथ मुख्य अभियंता को भेजा गया क्योंकि संवेदक का भुगतान नहीं होने की स्थिति में मामला न्यायालय में जा सकता था।
- (iii) कार्य पर हुए व्यय से संबंधित प्रपत्र—24 की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी थी तथा निर्णय लिया गया था कि आपातकालीन स्थिति में विभाग में निबंधित संवेदक से आपातकालीन स्थिति से गंगा नदी के कटाव से बुधुचक एवं विन्द टोली ग्राम को बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की गयी है। इसलिए संवेदक विभाग में निबंधन करा ले तथा कार्य की जॉच उड़नदस्ता से कराने के पश्चात ही व्यय के अनुमोदन की कार्रवाई की जाय।
- (iv) उड़नदस्ता ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि जल संसाधन विभाग में निबंधित संवेदक उपलब्ध नहीं होने पर आपातकालीन स्थिति में अन्य विभाग में निबंधित संवेदक से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराया गया। कराये गये कार्य कारगर सिद्ध हुए हैं तथा आगे की क्षति रोकी गयी है।
- (v) संवेदक द्वारा विभाग में निबंधन कराये जाने के पश्चात कराये गये कार्य के विरुद्ध आवंटन दिया गया एवं संवेदकों को भुगतान किया गया।
- (vi) आरोप गंभीर प्रकृति का नहीं है तथा सरकार को आर्थिक क्षति नहीं हुई है।
- (vii) अनिबंधित संवेदक से कार्य कराने वाले कार्यपालक अभियंता को विभाग ने आरोप मुक्त कर दिया है।

श्री राजेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सम्प्रति अभियंता प्रमुख (उत्तर) द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत निम्न तथ्य पाये गये :—

- (i) कार्यपालक अभियंता द्वारा अनिबंधित संवेदक से कार्य कराने की जानकारी प्रपत्र—24 प्राप्त होने के बाद हुई, इनका यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि एक ही जिला मुख्यालय के सारे पदाधिकारी है तथा कार्य भी हो रहा है, फिर भी जानकारी नहीं होने की बात स्वीकार योग्य नहीं है।
- (ii) कार्यपालक अभियंता के द्वारा की गयी भूल को सुधारने के बदले प्रपत्र—24 अनुशंसा कर इनके द्वारा भेजा गया।
- (iii) कार्य के दौरान अधीक्षण अभियंता के रूप में ये कार्य स्थल पर मौजूद रहे हैं और निर्देश देते रहे हैं। इसलिए इनका यह कथन कि प्रपत्र—24 प्राप्त होने पर मामले की जानकारी इनको हुई तथा इनके द्वारा कार्यपालक अभियंता के प्रस्ताव को मात्र अनुशंसा कर भेजा गया, स्वीकार योग्य नहीं है।
- (iv) निबंधित संवेदक के कार्य में अभिरुचि नहीं लेने तथा आपात स्थिति में अनिबंधित संवेदक से कार्य लेना जरूरी था तो इस आशय का प्रस्ताव उसी समय विभाग को भेजना था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया।
- (v) विभाग के निबंधित संवेदक द्वारा कार्य में अभिरुचि नहीं लेने के लिए उनके विरुद्ध इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

उपर्युक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में श्री राजेश कुमार का द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाया गया। फलस्वरूप उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राजेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल भागलपुर सम्प्रति अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना सं०-2413, दिनांक 09.11.16 द्वारा "एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त संसूचित दण्ड के आलोक में श्री राजेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल भागलपुर सम्प्रति अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया है —

- (1) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा अनिबंधित संवेदक से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य प्रारंभ करा दिया गया था जिसकी जानकारी प्रपत्र-24 के माध्यम से इन्हें 21 दिनों के पश्चात दी गयी।
- (2) अनिबंधित संवेदक से कार्य करवाकर दायित्व का सृजन करते हुए कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रपत्र-24 पर अनुशंसा कर इन्हें भेजा गया तथा इनके द्वारा प्रपत्र-24 उच्च पदाधिकारी को भेजने की विवशता उत्पन्न हो गयी थी।
- (3) बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जैसे आपातकालीन स्थिति में अधीक्षण अभियंता के रूप में इनके द्वारा कार्य स्थल पर आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए तथा बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करवाकर कटाव से गाँवों को बचाया गया। निरीक्षण के समय कार्यपालक अभियंता द्वारा अनिबंधित संवेदक के बारे में नहीं बताया गया।
- (4) निबंधित संवेदक के कार्य में अभिरुचि नहीं लेने की जानकारी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा ससमय उच्चाधिकारियों को नहीं दी गयी। इसके लिए कार्यपालक अभियंता शत-प्रतिशत दोषी प्रतीत होते हैं।
- (5) विभाग में निबंधित इच्छुक संवेदक से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने की प्रक्रिया है। यदि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा विभाग में निबंधित संवेदक द्वारा कार्य में अभिरुचि नहीं लेने के लिए इनके विरुद्ध प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को समर्पित किया जाता तो उचित कार्रवाई की गयी होती।

श्री राजेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल भागलपुर सम्प्रति अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दाखिल पुनर्विलोकन अर्जी में प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार ने अपने पुनर्विलोकन अर्जी में मुख्यतः उन्हीं तथ्यों की पुनरावृत्ति की है, जिसका उल्लेख इनके द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में है। पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया विचारणीय तथ्य नहीं दिया गया है, बल्कि पूर्व में ही कही गयी बातों की पुनरावृत्ति की गयी है।

उपर्युक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में श्री राजेश कुमार द्वारा दाखिल पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सरकार के स्तर पर लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेश कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल भागलपुर सम्प्रति अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का दाखिल पुनर्विलोकन अर्जी अस्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-2413, दिनांक 09.11.16 द्वारा पूर्व में अधिरोपित निम्न दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लेते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है।

"एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह, संयुक्त सचिव।

7 जून 2017

सं० 22/नि0सि0(पट0)-03-04/2017-866—श्री ख्वाजा जमाल नासीर, सहायक अभियंता, आई०डी०-4542, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, पटना को प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-1419, दिनांक 30.03.17 के आलोक में दिनांक 14.01.2017 को सबलपुर दियारा पतंग उत्सव के दौरान हुई नाव दुर्घटना के दिन प्रतिनियुक्ति स्थल से अनुपस्थित पाया गया। जिसके लिए श्री ख्वाजा जमाल नासीर को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-5789, दिनांक 16.05.17 के आलोक में विभाग के स्तर से लिये गये निर्णय के तहत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. श्री ख्वाजा जमाल नासीर को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।
3. श्री ख्वाजा जमाल नासीर का निलंबन अवधि में मुख्यालय मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।
4. श्री ख्वाजा जमाल नासीर के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्रपत्र-क गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।

27 जून 2017

सं० 22/नि०सि०(पट०)-03-04/2017-1032—श्री उमेश सिंह, कार्यपालक अभियंता, आई०डी०-3680, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, पटना को प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-1419, दिनांक 30.03.17 के आलोक में दिनांक 14.01.2017 को सबलपुर दियारा पतंग उत्सव के दौरान हुई नाव दुर्घटना के दिन प्रतिनियुक्ति स्थल से अनुपस्थित पाया गया। जिसके लिए श्री उमेश सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-5789, दिनांक 16.05.17 के आलोक में विभाग के स्तर से लिये गये निर्णय के तहत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. श्री उमेश सिंह को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

3. श्री उमेश सिंह का निलंबन अवधि में मुख्यालय मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

4. श्री उमेश सिंह के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्रपत्र-‘क’ गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश अलग से निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।

23 जून 2017

सं० 22/नि०सि०(भाग०)-09-15/2016-1029—श्री अरुण प्रकाश (आई०डी०-4400), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, चान्दन परियोजना प्रमण्डल, काडा, बाँका सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमण्डल, मोतिहारी के विरुद्ध प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष, के०वी०सी०, काडा, भागलपुर के पत्रांक-253, दिनांक 29.09.16 द्वारा अनुशासनहीनता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना तथा सरकारी कार्यों के प्रति उदासीन होने का आरोप प्रतिवेदित करने के आधार पर इनसे विभागीय पत्रांक 2419, दिनांक 15.11.16 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री प्रकाश द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक-35, दिनांक 15.02.2017 में अंकित किया गया है कि प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-अध्यक्ष के०वी०सी०, काडा, भागलपुर के पत्रांक-266, दिनांक 28.10.2014 द्वारा दिए गए निदेश के क्रम में पत्रांक-02, दिनांक 02.01.2015 द्वारा श्री संतोष कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, चान्दन परियोजना प्रमण्डल, काडा, बाँका के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना-आदमपुर (भागलपुर) से अनुरोध किया गया। किन्तु उन्हें प्राथमिकी संख्या नहीं मिला। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण उनके द्वारा दिनांक 03.10.2015 को पद का प्रभार अन्य पदाधिकारी को दे दिया गया।

श्री प्रकाश द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री प्रकाश को प्राथमिकी दर्ज कराने का निदेश दिया गया था तो उन्हें प्राथमिकी दर्ज कराकर थाना काण्ड संख्या के साथ प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। श्री प्रकाश जब तक बाँका में पदस्थापित रहे उन्होंने प्राथमिकी संख्या उच्चाधिकारी को नहीं दिया और न ही उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। जब नव पदस्थापित कार्यपालक अभियंता श्री विमल कुमार पदस्थापित हुए तो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उच्चाधिकारी को प्राथमिकी संख्या एवं प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध करायी। इस प्रकार श्री प्रकाश अनुशासनहीनता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना तथा सरकारी कार्यों के प्रति उदासीनता के दोषी हैं।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के सम्यक समीक्षोपरांत श्री अरुण प्रकाश, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, चान्दन परियोजना प्रमण्डल, काडा, बाँका सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमण्डल, मोतिहारी के विरुद्ध **“एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक”** का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से किया गया है।

अतः सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री अरुण प्रकाश, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, चान्दन परियोजना प्रमण्डल, काडा, बाँका सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमण्डल, मोतिहारी के विरुद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है।

“एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक”।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।

29 जून 2017

सं० 22/नि०सि०(पू०)-01-06/2014-1049—मुख्य अभियन्ता, पूर्णियाँ परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के अन्तर्गत वर्ष 2011 में झौआ-लाभा महानंदा दायों तटबंध के चैन संख्या 885-900 के बीच दिनांक 16.08.11 से 31.08.11 तक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने में बरती गयी अनियमितता के लिए श्री मोदनारायण चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2514, दिनांक 10.11.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोप के प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी, सम्यक समीक्षोपरांत श्री मोदनारायण चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के विरुद्ध लगाये गये आरोप को साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं पाते हुए आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतएव सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री मोदनारायण चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार सम्प्रति से0नि0 को लगाये गये उक्त आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।

29 जून 2017

सं० 22/नि0सि0(पू0)-21-04/2010-1050—श्री लक्ष्मण राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता नहर अंचल, पूर्णियाँ के विरुद्ध मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमण्डल, नरपतगंज के अन्तर्गत एकरारनामा सं० 25F2/2000-01 एवं 29F2/2000-01 के तहत श्री किशोर कुमार जायसवाल संवेदक के द्वारा सम्पादित कराये गये कार्यों के विरुद्ध विभागीय पत्रांक 353, दिनांक 03.03.2001 के आलोक में 40 प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया। शेष लंबित राशि के भुगतान हेतु समय-समय पर विभाग से आवंटन की माँग की गयी एवं 8 वर्षों के बाद लंबित भुगतान हेतु दायित्व समिति का गठन किया गया, जिसके आप अध्यक्ष/सदस्य थे, परंतु दायित्व समिति की बैठक में कलभर्ट के गुणवत्ता का जाँच नहीं किया गया का झूठ प्रतिवेदन अपने उच्चाधिकारियों एवं माननीय उच्च न्यायालय को देते हुए दावे को अमान्य कर दिया, साथ ही संवेदक को करीब 8 वर्षों की लंबी अवधि तक उनके द्वारा किये गये कार्यों के लंबित भुगतान को नहीं कर संवेदक को मानसिक एवं आर्थिक रूप से हानि पहुँचाने एवं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कर्तव्य का पालन नहीं करने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प 317 दिनांक 16.03.11 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें उन्होंने उपर्युक्त आरोप के प्रथम अंश दायित्व समिति के सदस्य के रूप में दिनांक 29.12.08, 30.12.08, 20.3.09 एवं 06.04.09 को हुई बैठक में संवेदक के कार्यों को अपूर्ण माने जाने, संवेदक के द्वारा कार्यों को ससमय पूरा नहीं किये जाने के कारण उड़नदस्ता संगठन से जाँच नहीं किये जाने के कारण संवेदक के दावे को अमान्य करते हुए विभाग को निर्णय लेने हेतु भेजे जाने वाले कार्यवाही प्रतिवेदन पर सदस्य के रूप में हस्ताक्षर अंकित होने के आरोप को प्रमाणित पाया।

श्री राम के के विरुद्ध उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन देते हुए विभागीय पत्रांक 2117, दिनांक 17.09.15 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री राम से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी, सम्यक समीक्षोपरांत श्री राम के विरुद्ध दायित्व समिति के सदस्य के रूप में दायित्व समिति के द्वारा संवेदक के दावे को अमान्य करने के लिए निर्णय लेने के आरोप को प्रमाणित पाया गया।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री लक्ष्मण राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, नहर अंचल, पूर्णियाँ को विभागीय अधिसूचना सं०-2651, दिनांक 27.12.16 द्वारा "एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक" का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री लक्ष्मण राम, अधीक्षण अभियंता द्वारा पुर्नविचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी, समीक्षा में कोई विचारणीय बिन्दु नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री लक्ष्मण राम, अधीक्षण अभियंता से प्राप्त पुर्नविचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में संसूचित दण्ड "एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक" को यथावत रखा जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।

29 जून 2017

सं० 22/नि0सि0(पू0)-01-06/2014-1051—मुख्य अभियन्ता, पूर्णियाँ परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के अन्तर्गत वर्ष 2011 में झोआ-लाभा महानंदा दायों तटबंध के चैन संख्या 885-900 के बीच दिनांक 16.08.11 से 31.08.11 तक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने में बरती गयी अनियमितता के लिए श्री उपेन्द्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2513, दिनांक 10.11.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी, समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री उपेन्द्र से विभागीय पत्रांक 1839, दिनांक 23.08.16 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री उपेन्द्र से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी, सम्यक समीक्षोपरांत श्री उपेन्द्र के विरुद्ध लगाये गये आरोप को साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं पाते हुए आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतएव सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री उपेन्द्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार सम्प्रति से0नि0 को लगाये गये उक्त आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।

30 जून 2017

सं० 22/नि0सि0(पू0)-01-11/2014-1058—श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ के विरुद्ध विभागीय पत्रांक-1262, दिनांक 28.05.15 द्वारा निम्नांकित आरोपो के लिए प्रपत्र-‘क’ के साथ स्पष्टीकरण पूछा गया :-

- (i) अवमाननाबाद सं०-3180/2011 राजेन्द्र चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में विभाग की ओर से कारण पृच्छा दायर करने में विभागीय तथ्यों से अलग हटकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कारण पृच्छा दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष विभागीय स्थिति कमजोर हो गयी, हालांकि MJC निरस्त हो गया किन्तु वादी को यह स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी कि वे अपने माँगों के संबंध में अन्य फोरम पर भी वस्तुस्थिति को रख सकते हैं।
- (ii) मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ द्वारा अपने पूरे परिक्षेत्र के समूह ‘घ’ के पद की रिक्तियों का आकलन करते हुए रिक्तियों की सूचना जिला समाहरणालय, पूर्णियाँ को भेजा गया, जबकि रिक्तियाँ पूर्णियाँ के अतिरिक्त कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला से संबंधित थी।
- (iii) कोषरक्षक एवं दफतरी के पदों पर सीधी नियुक्ति नहीं की जाती है बल्कि यह पद अनुसेवकों से भरा जाता है फिर भी इन पदों पर भी सीधी भर्ती हेतु अध्याचना की गई।

श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी, समीक्षा में पाया गया कि -

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियंता परिक्षेत्राधीन छटनीग्रस्त/कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण के मामला सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-639, दिनांक 16.03.06 एवं माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन रहने के कारण समूह ‘घ’ के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं किये जाने का स्पष्ट निदेश विभागीय पत्रांक-321, दिनांक 23.02.12 द्वारा परिचारित है। इसे बावजूद श्री चौधरी द्वारा MJC सं०-3180/2011 राजेन्द्र चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में विभाग द्वारा निरूपित तथ्य के विरुद्ध श्री चौधरी ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पूरक कारण पृच्छा दायर किया, जिसके कारण विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, इतना ही नहीं श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विभागीय स्टैण्ड से अलग कारण पृच्छा दायर किये जाने के कारण विभाग को माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय कारण पृच्छा करना पड़ा। इस प्रकार श्री चौधरी अवमाननावाद सं०-3180/2011 में विभागीय तथ्यों के प्रतिकूल कारण पृच्छा दाखिल करने के लिए दोषी पाये गये हैं।

पूर्णियाँ परिक्षेत्र के समूह ‘घ’ के रिक्तियों का रोस्टर क्लीयरेंस पर प्रमण्डलीय आयुक्त से अनुमोदन के उपरांत रिक्तियों का आकलन कर रिक्तियों की सूचना पूर्णियाँ के अतिरिक्त अन्य जिला से संबंधित रहने के कारण संबंधित समाहरणालय को भेजा जाना था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया है। इस तथ्य की स्वीकारोक्ति श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में दी गयी है।

इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-2599, दिनांक 21.12.16 द्वारा श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ को “दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक” का दण्ड संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्ड के विरुद्ध श्री सुरेश चौधरी, मुख्य अभियंता (सिंचाई सृजन) गया द्वारा पुनर्विचार आवेदन दिया गया। श्री चौधरी के प्राप्त पुनर्विचार आवेदन की समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य या कोई विचारणीय बिन्दु नहीं है। तदालोक में उनसे प्राप्त अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेश चौधरी मुख्य अभियंता (सिंचाई सृजन) गया से प्राप्त पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में संसूचित दण्ड “दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक को यथावत रखा जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन, संयुक्त सचिव।

सं० 6/श्रम वि० आ०-(02) 09/2014 श्र०सं०-1035

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

27 अप्रैल 2017

श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना, के विरुद्ध ‘बाबा सत्य साईं इंटरप्राइजेज’, पटना की मिली भगत से 2004 में बाढ़ राहत सामग्रियों के क्रय एवं वितरण में पटना

समाहरणालय द्वारा बरती गई अनियमितता के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या— 08/2005 दिनांक 28.05.2005 कायम किये जाने के कारण विभागीय संकल्प संख्या 06/श्रम वि०आ० 5013/05—343 दिनांक 03.11.2005 द्वारा निलंबित किये गये थे। तदोपरांत उनके विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के लिये विभागीय संकल्प संख्या 06/श्रम वि०आ० 5013/05—453 दिनांक 09.02.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

2. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरुद्ध यह आरोप गठित किया गया था कि श्री संजीव कुमार वल्द श्री रामानंद सिंह द्वारा दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत बाबा सत्य साईं इन्टरप्राइजेज, 405— अन्नपूर्णा बिहार, वेद नगर, रूकनपुरा, बेली रोड, पटना का निबंधन कराने हेतु दिनांक 24.04.2004 को आवेदन दिया गया परन्तु मूल आवेदन पत्र श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, श्रम अधीक्षक—सह निरीक्षी पदाधिकारी, पटना ने साजिश के तहत दिनांक 13.04.2004 को प्राप्ति दिखाया। प्रतिष्ठान का निरीक्षण किये बिना उन्होंने प्रतिष्ठान को कार्यरत बताया तथा दिनांक 26.04.2004 को उक्त फर्जी प्रतिष्ठान का निबंधन कर दिया एवं पद का भ्रष्ट दुरुपयोग किया।

3. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक—सह—निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री चन्द्र नाथ झा, तत्कालीन उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री झा के स्थानांतरण के पश्चात् विभागीय संकल्प संख्या 2242 दिनांक 28.06.2007 द्वारा श्री राम देव रजक, तत्कालीन संयुक्त श्रमायुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी श्री रामदेव रजक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को अस्वीकृत करते हुये विभागीय संकल्प संख्या 3153 दिनांक 13.10.2008 द्वारा श्री उपेन्द्र कुमार राय, श्रमायुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। परन्तु श्री उपेन्द्र कुमार राय के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विभागीय संकल्प संख्या 2000 दिनांक 23.08.2010 श्री गरीब साहू तत्कालीन अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. श्री गरीब साहू, तत्कालीन अपर सचिव—सह संचालन पदाधिकारी ने दिनांक 24.10.2011 को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरुद्ध गठित आरोप को पूर्णतः प्रमाणित पाया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त श्री महतो से विभागीय पत्रांक 280 दिनांक 01.02.2012 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री महतो ने द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर दिनांक 05.03.2012 प्रस्तुत किया जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त संतोषजनक एवं विश्वसनीय नहीं पाया गया। चूँकि श्री महतो के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, अतः उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का औपबंधिक निर्णय लिया गया।

5. श्री महतो के विरुद्ध अधिरोपित किये जाने वाले वृहत दण्ड पर विभागीय पत्रांक 2353 दिनांक 16.07.2013 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1424 दिनांक 27.09.2013 से प्राप्त परामर्श में आयोग द्वारा यह अभिमत दिया गया कि 'प्रस्तावित दण्ड आनुपातिक नहीं है। अतः आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करता है।' किन्तु आयोग ने सरकार के निर्णय से असहमति का यथेष्ट कारण नहीं बताया।

6. इसी बीच श्री बीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार को अपनी सेवा बर्खास्तगी को रोकने हेतु सीधे एक पत्र लिखा गया। विभाग द्वारा मामले की पुनः पूर्ण रूप से समीक्षा की गयी एवं बिहार लोक सेवा आयोग के मत से असहमत होते हुये श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरुद्ध भ्रष्ट आचरण एवं पद का दुरुपयोग के प्रमाणित आरोपों के कारण विभागीय संकल्प संख्या 6/श्रम वि० आ०— 5013/05 श्र०सं०—3892 पटना, दिनांक 15.10.2013 सह पठित संकल्प संख्या 6/श्रम वि० आ०— 5013/05 श्र०सं०— 622 पटना, दिनांक 22.02.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 की कंडिका—2 की उप कंडिका (xi) के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्त (**dismiss**) करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

7. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा उक्त दण्ड के विरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका दिनांक 20.11.2013 दायर की गयी थी। श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के पुनर्विलोकन याचिका की सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं यह पाया गया कि श्री महतो ने अपनी याचिका में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया है जो पूर्व में द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में दे चुके हैं। अतः सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री महतो के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया एवं विभागीय पत्रांक 6/श्रम वि० आ०— 5013/05 श्र०सं०— 4713 पटना, दिनांक 18.12.2013 द्वारा इसकी सूचना श्री महतो को दी गयी।

8. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 6/श्रम वि० आ०— 5013/05 श्र०सं०—3892 पटना, दिनांक 15.10.2013 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 3053/2014 बीरेन्द्र कुमार महतो बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17.11.2016 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्न रूपेण है—

For the reasons aforementioned, the resolution bearing Memo No. 3892 dated 15.10.2013 of the State Government as the disciplinary authority of the petitioner whereby an order of dismissal has been passed cannot be upheld and is accordingly quashed and set aside and for the same reason the order on review as communicated vide letter dated 18.12.2013 impugned at Annexure-2 becomes unsustainable and is quashed and set aside. The matter is remitted to the disciplinary authority to pass an order afresh but in accordance with law and bearing in mind of observations made hereinabove.

9. माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 241 दिनांक 09.01.2017 द्वारा श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक—सह—निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना, के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 6/श्रम वि० आ०— 5013/05 श्र०सं०—3892 पटना, दिनांक 15.10.2013

सह पठित संकल्प संख्या 6/श्रम वि० आ०- 5013/05 श्र०सं०- 622 पटना, दिनांक 22.02.2014 द्वारा अधिरोपित दण्ड को रद्द करते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा मामले पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया गया।

10. सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने इनके विरुद्ध गठित आरोप को इस आधार पर पूर्णतः प्रमाणित पाया है कि बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान के तहत आवेदन प्राप्ति की कोई स्थापित व्यवस्था कार्यालय में नहीं थी तथा आवेदन प्राप्ति का कोई रसीद, डायरी पंजी आदि संचारित नहीं थी आवेदन सीधे संबंधित पदाधिकारी द्वारा स्वयं प्राप्त कर उस पर लघु हस्ताक्षर प्राप्ति की तिथि दर्शाते हुये अंकित की जाती थी तथा अग्रेतर कार्यवाई हेतु संबंधित लिपिक को दी जाती थी वर्तमान मामले में भी इसी प्रक्रिया का अनुपालन किया गया। संबंधित लिपिक द्वारा शुल्क पंजी में आवेदन प्राप्ति की तिथि 24.04.2004 अंकित किया गया है जिसका कारण आरोपित पदाधिकारी एवं संबंधित लिपिक द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका। उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक 380 दिनांक 09.02.2011 द्वारा यह सूचित किया गया है आवेदन प्राप्ति की तिथि शुल्क पंजी में ही अंकित की जाती है। अतः यह तथ्य प्रमाणित है कि बाबा सत्य साईं इन्टरप्राइजेज, 405- अनपूर्णा बिहार, वेद नगर, रुकनपुरा, बेली रोड, पटना का निबंधन हेतु आवेदन दिनांक 24.04.2004 को ही प्राप्त हुआ था, परन्तु साजिश के तहत उक्त आवेदन प्राप्ति की तिथि दिनांक 13.04.2004 दिखायी गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रतिष्ठान के निबंधन हेतु समर्पित आवेदन में दुकान खुलने की तिथि 12.03.2004 अंकित है। नियमानुसार दुकान खुलने के एक महीने के अंदर प्रतिष्ठान का निबंधन सुनिश्चित करने हेतु आरोपित पदाधिकारी द्वारा आवेदक से मिलकर आवेदन प्राप्ति की तिथि 13.04.2004 अंकित की गयी। आवेदक द्वारा इसी कारणवश आवेदन में अपने हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं की गयी जो विहित आवेदन प्रपत्र में अंकित करना आवश्यक है।

जाँच प्रतिवेदन में यह भी अंकित है कि बाबा सत्य साईं इन्टरप्राइजेज, पटना का बिना निरीक्षण किये कार्यरत बताने तथा निबंधन करने के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह कहा गया था कि उनके द्वारा प्रतिष्ठान का दिनांक 19.04.2004 को निरीक्षण करने के बाद आवेदक को कार्यालय में आकर आवेदन प्रपत्र में पिता का नाम अंकित करने का निर्देश दिया गया था तथा उक्त त्रुटि सुधार के बाद ही निबंधन किया गया। संचालन पदाधिकारी की राय में यदि आरोपित पदाधिकारी के इस कथन को सत्य भी माना जाये तो भी यह संदेहास्पद है कि एक आवासीय अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर स्टेशनरी एवं आर्डर सप्लायर का दुकान अवस्थित था तथा जिसे श्रम अधीक्षक द्वारा दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में परिभाषित दुकान एवं प्रतिष्ठान मानते हुये निबंधन के योग्य पाया गया। जब निबंधन हेतु प्राप्त आवेदन अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण था तो आवेदन के त्रुटि निराकरण के पूर्व ही आरोपित पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना किस प्रकार विश्वसनीय कहा जा सकता है। सामान्य रूप से अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर या तो उसे अस्वीकृत किया जा सकता था अथवा आवेदन को विधिवत त्रुटि निराकरण का लिखित आदेश दिया जा सकता था परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा संतुष्ट होने के कारण के रूप में यह भी कहा है कि उक्त प्रतिष्ठान का दिनांक 09.04.2004 को आई०डी०बी०आई बैंक पटना में खाता एवं सात लाख रुपये से अधिक राशि जमा होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध था, परन्तु आई०डी०बी०आई बैंक में खाता होने मात्र से यह किस प्रकार मान्य हो सकता है कि कोई प्रतिष्ठान विधिवत स्थापित है तथा बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अधीन निबंधन के योग्य है। निगरानी ब्यूरो द्वारा इस संबंध में अपने प्रतिवेदन में जो शंका व्यक्त की गयी है वह सार्थक प्रतीत होती है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव में जो साक्ष्य समर्पित किये हैं उनसे बचाव पक्ष को कोई बल नहीं मिलता है एवं श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के विरुद्ध आरोप पूर्णतः प्रमाणित होते हैं।

11. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर दिनांक 05.03.2012 तथा पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 20.11.2013 में अपने बचाव में यह उल्लेख किया है कि बाबा सत्य साईं इन्टरप्राइजेज का आवेदन पत्र दिनांक 13.04.2004 को ही प्राप्त हुआ था, दिनांक 24.04.2004 को नहीं। किन्तु आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण रहने के कारण उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। दिनांक 19.04.2004 को उसी मोहल्ले में अपने वरीय पदाधिकारी श्री अशोक कुमार से व्यक्तिगत कार्य से मिलने गये थे उसी क्रम में उक्त प्रतिष्ठान में जाकर आवेदन को भूल सुधार के लिये बताया। इसके पश्चात् दिनांक 26.04.2004 को हस्ताक्षर किया। यदि आवेदन दिनांक 24.04.2004 को प्राप्त होता तो किस आधार पर निबंधन पंजी तथा निबंधन प्रमाण पत्र में निबंधन की तिथि दिनांक 13.04.2004 अंकित किया जा सकता था।

श्री महतो के अनुसार संचालन पदाधिकारी उनके विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे एवं उनके द्वारा तथ्यों का गलत ढंग से प्रतिवेदित किया गया है। उप श्रमायुक्त, पटना के पत्रांक 380 दिनांक 09.02.2011 की जांच एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान उनको उपलब्ध नहीं कराया गया तथा संबंधित लिपिक द्वारा दिये गये बयान कि उसकी गलती से शुल्क प्रविष्टि करने की तिथि के बदले आवेदन प्राप्ति की तिथि अंकित हो गयी थी पर संचालन पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया। श्री महतो ने यह भी उल्लेख किया है कि प्रासंगिक प्रतिष्ठान के निबंधन हेतु प्राप्त आवेदन में दुकान खुलने की तिथि 12.03.2004 अंकित है एवं नियमानुसार दुकान खुलने की तिथि की एक माह के अंदर प्रतिष्ठान का निबंधन आवश्यक है। परंतु बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 के नियमावली, 1955 के अनुसार विलंब शुल्क के साथ आवेदन कभी भी दिया जा सकता है। अतः संचालन पदाधिकारी का यह मंतव्य कि दुकान खुलने की तिथि से एक माह के अंदर प्रतिष्ठान का निबंधन सुनिश्चित करने के लिये आवेदक से मिलकर आवेदन दिनांक 13.04.2004 को दर्शाया गया युक्तिसंगत नहीं है।

श्री बीरेन्द्र कुमार महतो ने यह भी उल्लेख किया कि बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 एवं नियमावली, 1955 के अंतर्गत आवासीय अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर अवस्थित प्रतिष्ठान का निबंधन वर्जित नहीं है तथा प्रासंगिक अधिनियम एवं नियमावली में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि निबंधन के पूर्व किसी प्रतिष्ठान का निरीक्षण नहीं किया जा सकता। उपरोक्त के अतिरिक्त श्री महतो ने यह भी कहा है कि नियोजक द्वारा दिये गये आवेदन असंतुष्ट होने का

कोई कारण नहीं था। जबकि संतुष्ट होने के कारण में उल्लेख किया गया था कि नियोजक द्वारा आई0डी0बी0आई बैंक में प्रासंगिक प्रतिष्ठान के नाम पर सात लाख रुपये से अधिक की राशि जमा कर दिनांक 09.04.2004 का खाता खुलवाया था। उन्होंने परिसर में स्वयं जाकर देखा था कि प्रतिष्ठान अवस्थित है एवं इसी निरीक्षण के परिणामस्वरूप नियोजक द्वारा अपने आवेदन में पिता का नाम अंकित किये जाने के पश्चात् दिनांक 26.04.2004 को निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।

12. श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना द्वारा अपने बचाव में जो भी तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं उनपर सक्षम प्राधिकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया। यह उल्लेखनीय है कि श्री बीरेन्द्र कुमार महतो यह स्वयं दलील दे रहे हैं कि उन्हें बाबा सत्य साईं इन्टरप्राइजेज का आवेदन दिनांक 13.04.2004 को प्राप्त हुआ था और वह त्रुटिपूर्ण था। जब श्री महतो के संज्ञान में आवेदन पत्र की त्रुटि उसी दिन आ गयी थी तो फिर उन्होंने त्रुटि सुधार के लिये आवेदक को लिखित सूचना क्यों नहीं दी। सरकारी कार्य लिखित रूप में संपादित होता है। इसलिये यदि आवेदन में कोई त्रुटि थी तो उसकी लिखित सूचना आवेदक को श्री महतो के द्वारा ससमय देनी चाहिए थी और उसका निराकरण लिखित रूप में आने के बाद उसके निबंधन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परन्तु श्री बीरेन्द्र कुमार महतो के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस प्रकार पिछली तिथि में आवेदन प्राप्त करने के आरोप को श्री महतो द्वारा छुपाया नहीं जा सकता।

प्रासंगिक मामला वर्ष 2004 में बाढ़ राहत योजना के अंतर्गत एक फर्जी फर्म बाबा सत्य साईं इन्टरप्राइजेज की मिली भगत से बाढ़ राहत सामग्रियों के क्रय एवं वितरण के मामले में बरती गयी अनियमितता से संबंधित है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि श्री बीरेन्द्र कुमार महतो द्वारा बाबा सत्य साईं इन्टरप्राइजेज का निबंधन साजिशपूर्ण षडयंत्र के तहत बाबा सत्य साईं इन्टरप्राइजेज को अवैध लाभ पहुँचाने हेतु किया गया एवं इस क्रम में फर्जी कागजात तैयार किये गये। बाबा सत्य साईं इन्टरप्राइजेज के उर्पयुक्त पते पर ब्यूरो द्वारा भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि वस्तुतः 405- अन्नपूर्णा बिहार, वेद नगर, रुकनपुरा, पटना एक आवासीय प्लैट था एवं वहाँ पर कभी भी कोई व्यवसायिक कार्य उस प्लैट के मालिक संतोष कुमार झा के द्वारा नहीं किया गया। स्पष्टतः इस पुरे मामले में श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक द्वारा साजिशपूर्ण ढंग से उस फर्जी फर्म को अवैध रूप से निबंधित किया गया। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है। अतः श्री महतो के विरुद्ध गठित आरोप पूर्णतः प्रमाणित होता है। प्रासंगिक मामले में बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श भी प्राप्त किया गया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग, विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमत नहीं था परन्तु आयोग सरकार के निर्णय से अपनी असहमति का कोई यथेष्ट कारण नहीं बता सका। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री महतो द्वारा माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को अपनी सेवा बर्खास्तगी को रोकने हेतु सीधे एक पत्र लिखा गया था, जो सरकारी सेवक के आचारण के प्रतिकूल है। अतः श्री महतो के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी का जो दंड अधिरोपित किया गया है वह युक्तिसंगत है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना सम्प्रति श्रम अधीक्षक (निलंबित), श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 6/श्रम वि० आ०- 5013/05 श्र०सं०- 3892 पटना, दिनांक- 15.10.2013 सह पठित संकल्प संख्या 6/श्रम वि० आ०- 5013/05 श्र०सं०- 622 पटना, दिनांक- 22.02.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियमावली, 2007 के नियम 14 (xi) के अन्तर्गत दिनांक 15.10.13 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्त (dismiss) करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री बीरेन्द्र कुमार महतो, तत्कालीन श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षी पदाधिकारी, उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना सम्प्रति श्रम अधीक्षक (निलंबित), श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना को निबंधित डाक से उपलब्ध कराये।

विवरणी:-

1. नाम:- श्री बीरेन्द्र कुमार महतो
2. पिता का नाम:- स्व० बाबूजी महतो
3. जन्म तिथि:- 20.01.1965
4. बर्खास्तगी की तिथि:- 15.10.2013
5. सेवा का नाम- बिहार श्रम सेवा (सामान्य)
6. स्थायी पता- ग्राम, पो०- खिरहर बाजार,
थाना- खिरहर, भाया बेनीपट्टी, जिला- मधुबनी।
7. वर्तमान पता- श्रमायुक्त का कार्यालय, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह, अपर सचिव।

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचनाएं
29 मई 2017

सं० 2/अ०प्र०-2-44/2014-1061—श्री रामचन्द्र पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज को मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनांतर्गत वर्ष-2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में कार्य प्रमंडल, इमामगंज के अधीन कार्यान्वयन हेतु दी गयी परियोजनाओं में से 10 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण नहीं करके उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित रखने के लिए जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 34/बी-21मु०/वि० दिनांक 25.01.2014 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुशांसा उपलब्ध करायी गयी।

जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय पत्रांक 335 अनु० दिनांक 23.07.2014 द्वारा श्री पासवान से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री पासवान के पत्रांक 261 दिनांक 06.06.2014 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। श्री पासवान द्वारा स्पष्टीकरण में संदर्भित परियोजनाओं का कार्यान्वयन लंबित रहने संबंधी परिस्थितियों एवं कारणों से जिला पदाधिकारी, गया को अवगत कराने तथा सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र उग्रवादी गतिविधियों के दृष्टिकोण से अतिसंवेदनशील होने जैसे तथ्यों का उल्लेख किया गया।

श्री पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 2353 अनु० दिनांक 23.07.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, गया का पत्रांक 116मु०/वि० दिनांक 13.10.2014 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। मंतव्य में उल्लेख किया गया कि जिन परियोजनाओं के लंबित रहने के कारण श्री पासवान के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया उन सभी में दिनांक 03.05.2010 से 04.11.2011 के बीच प्रशासनीक स्वीकृति दी गयी। श्री पासवान दिनांक 04.07.2013 तक कार्य प्रमंडल, इमामगंज के प्रभार में रहे। इस प्रकार श्री पासवान को परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त समय मिला परन्तु उनके द्वारा एक भी योजना पूर्ण नहीं करायी गयी और न ही प्रगति प्रतिवेदन में लंबित रहने का कारण बताया गया। जिला पदाधिकारी, गया द्वारा श्री पासवान को स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाया गया।

जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री पासवान के विरुद्ध विभाग के स्तर से उन्हीं बिन्दुओं पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर पत्रांक 3351 दिनांक 24.09.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

उक्त के आलोक में श्री रामचन्द्र पासवान, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज को उनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उन पर जिला पदाधिकारी, गया के मंतव्य के समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14(i) एवं (v) के तहत निम्नांकित शास्ति संसूचित की जाती है :—

- (i) निंदन (आरोप वर्ष-2012-13)
- (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शंभू चौधरी, उप-सचिव।

15 जून 2017

सं० 3 अ०प्र०-1-184/10-1273—श्री सुदर्शन राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता-सी/5, साकेत विहार, मित्रमंडल कॉलनी, अनिसाबाद, पटना-2 द्वारा कार्य प्रमंडल, हिलसा अन्तर्गत पदस्थापन काल में छड़ो की नीलामी में बरती गयी अनियमितता के संबंध में आरोप पत्र प्रपत्र-क' गठित कर स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण की तकनीकी समीक्षा किये जाने के उपरान्त यह पाया गया कि सामानों के निस्तार सिर्फ नीलामी की प्रक्रिया अपनाकर ही किया जाना था, परन्तु नीलामी की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। चूँकि इस मामले में नीलामी नहीं की गयी, जिससे राजस्व की हानि के संबंध में आकलन संभव नहीं हो सका, परन्तु दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के लिए श्री राम को दोषी पाया गया है।

उक्त के आलोक में श्री सुदर्शन राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा को अधिसूचना संख्या-4335-सह-पठित ज्ञापांक 4336 दिनांक 26.11.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14 के कंडिका (v) के आलोक में असंचयात्मक प्रभाव से 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित की गयी।

उक्त दण्डादेश के आलोक में महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा उनके पत्रांक 979 दिनांक 13.01.2015 के माध्यम से सूचित किया गया है कि श्री राम की जन्म तिथि 01.07.1955 है एवं सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.2015 है। इस तरह से उक्त दण्ड का अनुपालन नहीं हो पा रहा है साथ ही यह अनुरोध किया गया कि उक्त अधिसूचना के आलोक में स्पष्ट निर्णय से उन्हें अवगत कराया जाय।

तदआलोक में समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा श्री राम के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के देखते हुए उनके सेवा को संतोषजनक नहीं मानते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत उनके पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती अगले 10 वर्षों तक करने का निर्णय लेते हुए सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर विभागीय पत्रांक 3809 दिनांक 26.12.2016 द्वारा श्री राम को उनके पेंशन में प्रस्तावित कटौती के बिन्दु पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। श्री राम द्वारा पेंशन में कटौती के बिन्दु पर रखे गये पक्ष में यह उल्लेख किया गया कि पेंशन नियमावली के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये बिना नियम 139 के तहत पेंशन से कटौती किये जाने का निर्णय नियमानुकूल नहीं है। श्री राम द्वारा समर्पित उक्त तथ्यों की विभागीय समीक्षा की गयी, समीक्षोपरान्त श्री सुदर्शन राम, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता के बचाव बयान को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत पेंशन से कटौती से विनिश्चित दण्ड के मामले में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति अथवा अभिमत प्राप्त किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः उक्त आलोक में सम्यक समीक्षोपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत श्री सुदर्शन राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता—सी/5, साकेत विहार, मित्रमंडल कॉलनी, अनिसाबाद, पटना-2 के विरुद्ध निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है:—

पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती अगले 10 वर्षों तक

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शंभू चौधरी, उप—सचिव।

समाहरणालय, मुंगेर
(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

7 सितम्बर 2016

सं० 31-5/2015-849/स्था०—श्री केदार प्रसाद जमादार, कार्यालय परिचारी, अनुमंडल कार्यालय, सदर मुंगेर की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1676/स्था०, दिनांक 27.12.2013 द्वारा की गई। उक्त आदेश के आलोक में श्री जमादार को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 856/स्था०, दिनांक 26.08.2014 द्वारा अनुमंडल कार्यालय सदर मुंगेर में पदस्थापित करते हुए किशोर न्याय परिषद, मुंगेर में प्रतिनियुक्त किया गया था। उनके द्वारा किशोर न्याय परिषद, मुंगेर में योगदान नहीं देकर अनुमंडल कार्यालय, सदर मुंगेर में दिनांक 29.08.2014 को योगदान दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर द्वारा श्री जमादार को दिनांक 06.09.2014 से किशोर न्याय परिषद, मुंगेर में योगदान देने हेतु विरमित किया गया। उनके द्वारा किशोर न्याय परिषद मुंगेर में अपना योगदान नहीं दिया। योगदान नहीं देने के फलस्वरूप श्री जमादार को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण भी पूछा गया था, परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब भी नहीं दिया गया। श्री जमादार को मुख्यालय से बिना सूचना के फरार रहने के आरोप में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 274/स्था०, दिनांक 11.03.2015 द्वारा निलंबित करते हुए मुख्यालय जिला स्थापना शाखा, मुंगेर निर्धारित किया गया लेकिन श्री जमादार कभी भी अपने मुख्यालय कार्यालय जिला स्थापना शाखा, मुंगेर में उपस्थित नहीं हुए। निलंबन के उपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर के द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' का गठन किया गया।

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 584/स्था०, दिनांक 22.06.2015 द्वारा श्री जमादार के विरुद्ध आरोप प्रपत्र 'क' पर विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु डॉ० ईश्वर चन्द्र शर्मा, अपर समाहर्ता-सह-अपर समाहर्ता विभागीय जांच मुंगेर को संचालन पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

अपर समाहर्ता, मुंगेर के पत्रांक 104/गो०, दिनांक 14.12.2015 एवं पत्रांक 109/गो० दिनांक 22.12.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री जमादार विगत कई तिथियों से संचालन पदाधिकारी के समक्ष अनुपस्थित है। संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 21/स्था०, दिनांक 08.01.2016 द्वारा विशेषदूत के माध्यम से निदेश दिया गया। दिनांक 09.01.2016 को श्री जमादार के द्वारा पत्र भी प्राप्त किया गया। पत्र प्राप्त होने के उपरान्त भी श्री जमादार संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, मुंगेर ने अपने पत्रांक 24/गो०, दिनांक 17.03.2016 द्वारा श्री जमादार के विरुद्ध आरोप प्रपत्र 'क' पर विभागीय कार्यवाही संचालित कर अपना प्रतिवेदन-सह-मंतव्य उपलब्ध कराया है। श्री जमादार के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित पाया गया है। गठित आरोप प्रपत्र 'क', उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की समेकित विवरणी निम्नांकित है:—

क्र० सं० 1	आरोप का विवरण 2	श्री जमादार का कारण पृच्छा	उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य 3	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य 4
1.	अनुमंडल कार्यालय, मुंगेर में योगदान के फलस्वरूप अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित	अप्राप्त	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर ने अपने ज्ञाप सं०-1261, दिनांक 06.09.2014 से श्री जमादार को प्रतिनियुक्त कार्यालय किशोर न्याय परिषद्, मुंगेर में योगदान देने हेतु दिनांक 06.09.2014 के अपराह्न में विरमित किया, परन्तु प्रभारी पदाधिकारी, बाल संरक्षण इकाई, मुंगेर ने पत्र सं०-434, दिनांक 18.09.2014 से जिला स्थापना शाखा, मुंगेर को सूचित कर रहे हैं कि न्यायालय में परिचारी के नहीं रहने से काफी कठिनाई हो रही है। पुनः उन्होंने पत्र सं०-503, दिनांक 07.11.2014 से जिला स्थापना शाखा को सूचित किया गया कि भवदीय आदेश के बावजूद श्री जमादार अवतक योगदान नहीं किये है।	अभिलेख एवं उसमें संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि श्री जमादार अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर द्वारा विरमित करने के बाद भी दिनांक 18.09.2014 तक किशोर न्याय परिषद्, मुंगेर में योगदान नहीं किये। इतना ही नहीं प्रभारी पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुंगेर के पत्र सं०-503 दिनांक 07.11.2014 से स्थापना उप समाहर्ता को सूचित किया गया है श्री जमादार अवतक योगदान नहीं किये। साथ ही जिला स्थापना शाखा के पत्र सं०-67 दिनांक 20.01.2016 से यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि श्री जमादार दिनांक 06.07.2015 को इस कार्यालय में योगदान किया और योगदान देने के दिन से वे आजतक अनुपस्थित हैं। यहाँ तक कि विभागीय कार्रवाई में भी लगातार आजतक अनुपस्थित हैं। इससे प्रतीत होता है कि वे आदत्तन भगौड़ा कर्मी है। अतः यह आरोप इनपर स्वतः प्रमाणित होता है।
2.	किशोर न्याय परिषद्, मुंगेर में योगदान नहीं करने तथा मुख्यालय से बिना सूचना के फरार है।	अप्राप्त	इस आरोप के विरुद्ध संलग्न साक्ष्य। स्थापना उप समाहर्ता, मुंगेर के आदेश ज्ञापक-1215, दिनांक 24.11.2014, 1290/स्था०, दिनांक 12.12.2014 एवं जिला पदाधिकारी के आदेश ज्ञापक 274/स्था०, दिनांक 11.03.2015 द्वारा अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण।	स्थापना उप समाहर्ता, मुंगेर के आदेश ज्ञापक-1215, दिनांक 24.11.2014 से श्री जमादार को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण पुनः स्थापना उप समाहर्ता के ज्ञाप सं०-1290/स्था०, दिनांक 12.12.2014 से स्पष्टीकरण पूछा गया, फिर भी कोई प्रतिउत्तर नहीं मिलने के कारण जिला पदाधिकारी ने श्री जमादार को ज्ञाप सं०-274/स्था०, दिनांक 11.03.2015 से कार्य के प्रति उदासीनता एवं अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया। यहाँ पर चल रहे विभागीय कार्रवाई में उनके द्वारा आजतक कोई अभिरुचि नहीं दिखाई गयी और लगातार अनुपस्थित है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वे अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन एवं लापरवाह है। अतः यह आरोप भी इनपर प्रमाणित होता है।

संचालन पदाधिकारी से श्री जमादार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के पश्चात श्री जमादार से विभागीय कार्यवाही में कोई अभिरुचि नहीं लेने और लगातार अनुपस्थित रहने के संबंध में इस कार्यालय के ज्ञापक 402/स्था०, दिनांक 20.04.2016 द्वारा स्थापना उप समाहर्ता, मुंगेर के समक्ष उपस्थित होने हेतु निबंधित डाक से अंतिम रूप से सूचना भी दी गई। इसके बावजूद श्री जमादार उपस्थित नहीं हुए।

श्री जमादार को उपस्थित होने हेतु दिनांक 19.07.2016 को प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण के विज्ञापन के माध्यम से सूचना प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित किये गये सूचना में श्री जमादार को एक सप्ताह के अन्दर उपस्थित होने हेतु निदेश दिया गया था। उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जायेगी की भी सूचना प्रकाशित किया गया था। परन्तु सूचना प्रकाशित होने के पश्चात् भी श्री जमादार दिनांक 20.08.2016 तक स्थापना उप समाहर्ता, मुंगेर के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

निष्कर्ष:-

श्री केदार प्रसाद जमादार, कार्यालय परिचारी, अनुमंडल कार्यालय, सदर मुंगेर प्रतिनियुक्त किशोर न्याय परिषद् मुंगेर के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप, उपलब्ध साक्ष्य, संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं संचिका में पोषित कागजातों पर सम्यक विचारोपरांत श्री जमादार, कार्यालय परिचारी द्वारा योगदान नहीं देना, अनाधिकृत अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता एवं अनैतिकता का परिचायक होने

का आरोप प्रमाणित होता है, श्री जमादार को कार्यों में कोई अभिरुचि नहीं है ना ही कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखते है और न ही सेवा में बने रहने की इनको कोई परवाह है। ऐसी स्थिति में वे सरकारी सेवा में बने रहने योग्य नहीं है तथा इन्हें कठोरतम दण्ड देने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। उपरोक्त साक्ष्य श्री जमादार की सेवा बर्खास्तगी का पर्याप्त आधार है।

अतः उक्त वर्णित सभी बिन्दुओं पर प्रमाणित आरोप के आलोक में गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए मै उदय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता, मुंगेर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथा संशोधित-2007 के नियम 14 (xi) में निहित शास्तियों के आलोक में श्री केदार प्रसाद जमादार, निलंबित कार्यालय परिचारी, मुंगेर को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से **बर्खास्त (Dismiss)** करता हूँ।

श्री केदार प्रसाद जमादार, कार्यालय परिचारी से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:-

1. कर्मचारी का नाम :-श्री केदार प्रसाद जमादार
2. पिता का नाम :-स्व0 राम प्रसाद जमादार
3. पद का नाम :-कार्यालय परिचारी
4. कार्यालय का नाम :-अनुमंडल कार्यालय, सदर मुंगेर प्रतिनियुक्त किशोर न्याय परिषद, मुंगेर
सम्प्रति मुख्यालय जिला स्थापना शाखा, मुंगेर
5. वेतनमान :-5200-20200 ग्रेड पे 1650
6. स्थाई पता :-मकईपुर, थाना कोढ़ा जिला-कटिहार (बिहार)

आदेश,

(ह0) अस्पष्ट, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, मुंगेर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 18—571+15-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>